



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 99]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 18, 1977/ज्येष्ठ 28, 1899

No. 99]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18, 1977/JYAISTHA 28, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(प्राथमिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 जून, 1977

सं० फा० 18](37)-डी० (डी०)/77.—वित्त मंत्री द्वारा 17 जून, 1977 को लोक सभा में दिये गये भाषण का निम्नलिखित मूल रूप में —

बजट 1977-78

वित्त मंत्री का भाषण

17 जून, 1977

(भाग “क”)

महोदय,

1. मैं 1977-78 का बजट पेश करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, यह पहला बजट है जो यह जनता सरकार पेश कर रही है।

2. इस वर्ष मार्च के महीने में भारत के लोगो ने जनता पार्टी को जो भारी अधिदेश (मैण्डेट) दिया था वह निरंकुशता के विरुद्ध मतदान मात्र नहीं था। बल्कि वह हमारे लोगो की इस इच्छा की अभिव्यक्ति भी थी कि हमारी आर्थिक नीतियो को नई दिशा और नया रूप दिया जाए जिससे कि गरीबी और निराश्रयता को जल्दी से खत्म किया जा सके। पिछले कुछ सप्ताहों में हमारी सरकार ने उस निरंकुश और दमनकारी ढांचे को तोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं जो आपात काल के काले दिनों में बनाया गया था। हमारा पक्का विश्वास है कि जिस खुले समाज की हम कामना करते हैं वह तब तक असुरक्षित रहेगा जब तक कि हम अपनी इस पुरातन भूमि में से गरीबी, अज्ञान और बीमारी को निकाल बाहर करने के लिए हिम्मत और सच्चे मन से आगे नहीं बढ़ सकने। हमारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में एक सामाज्यपूर्ण अर्थ-नीति बताई गई है जिसमें रोटी और आजादी दोनों पर जोर दिया गया है। हम आर्थिक प्रगति की रफ्तार को तेज करना चाहते हैं और उसके फलों को लोकनम्र और वैयक्तिक स्वतंत्रता के ढांचे में रहते हुए सबको समान रूप से बांटना चाहते हैं। पुराने ऐतिहासिक उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए तो यह निस्संदेह एक बहुत ही चुनौतीभरा काम है। सदन आश्वस्त रहे कि हमने अपनी जनता को जो वचन दिए हैं उन्हें पूरा करने के लिए काम करने के हमारे सच्चे इरादे को किसी प्रकार कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।

3. केन्द्रीय सरकार का बजट देश की सामाजिक और आर्थिक नीतियो को रूप देने का एक बड़ा साधन है। समय की कमी के कारण और चालू परियोजनाओं पर भारी खर्चा करने की वचनबद्धताओं की वजह से, मेरे लिए यह संभव नहीं हुआ है कि मैं राजकोषीय ढांचे को हमारी घोषित प्राथमिकताओं के अनुरूप फिर से ढाल सकूँ। इसके अलावा मुझे योजना आयोग से, जिसका पुनर्गठन अभी हाल ही में हुआ है, परामर्श करने का भी सुयोग नहीं मिला है। हमारी पार्टी के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम में ग्रामीण विकास हरिजनो आदिवासियों और अन्य पददलित वर्गों की दशा में सुधार, बरोजगारी को समाप्ति और गंदी बस्तियों की सफाई सहित सामाजिक सेवाओं के विस्तार पर बहुत जोर दिया गया है। इन कार्यक्रमों की अधिकतर परियोजनाएँ राज्यों की आयोजनाओं के अंतर्गत आती हैं। उन कारणों से, जिनका इस सदन को भली भाँति पता है, मेरे लिए यह संभव नहीं हुआ है कि मैं राज्य सरकारों के साथ परामर्श करता और उनको हमारी प्राथमिकताओं के अनुसार उनके विकास कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए तैयार कर लेता। फिर भी मेरे सामने जो सीमित संसाधन हैं उनकी परिधि में रहते हुए मैंने अपने बजट प्रस्तावों को इस प्रकार बनाने की कोशिश की है कि उनसे हमारे चुनाव घोषणापत्र में निर्दिष्ट सिद्धान्तों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को सही-सही प्रतिबिम्बित किया जा सके।

4. इससे पहले की मैं अपनाई गई नीति की रूपरेखा को मोटे तौर पर प्रस्तुत करूँ, मैं सदन को अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और मभावनाओं के बारे में अपने विचार बतलाना चाहूँगा। आर्थिक समीक्षा में इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा की गई है, इसलिए मैं यहाँ पर संक्षेप में ही अपने विचार प्रकट करूँगा।

5. भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे मूलभूत समस्या यही बनी हुई है कि आर्थिक वृद्धि की दर अपर्याप्त रही है। 1976-77 में आर्थिक वृद्धि की दर 2 प्रतिशत से कम थी। आठवें दशक में अब तक आर्थिक वृद्धि की वार्षिक औसत दर लगभग 3.5 प्रतिशत रही है। जो कि आयोजना के लक्ष्य से काफी कम है। और यद्यपि यह कहना गलत होगा कि स्वतंत्र

होने के बाव से हमारे देश ने कोई खास प्रगति नहीं की है फिर भी, तथ्य यही है कि पच्चीस वर्ष की योजनाओं के बाद भी हम 5 प्रतिशत की औसत वृद्धि-दर को बराबर बनाए नहीं रख सकते। अतः स्पष्ट है कि हमें अपनी आयोजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं और तकनीकों की नए सिरे से जांच करनी होगी।

6. आर्थिक स्थिति के बारे में दूसरी परेशान करने वाली बात यह है कि वृद्धि सब जगह एक जैसी नहीं हुई है जिसके कारण विकास के स्तर में क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ गई हैं। पिछले पंद्रह सालों में कई राज्यों में वृद्धि की दर बढ़िया रही है तथापि, यह सच है कि इसी अवधि में लगभग एक-तिहाई जिलों में वास्तव में पैदावार में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है बल्कि कहीं कहीं तो पैदावार पहले से भी कम हुई है। यह एक गंभीर चिन्ता का विषय है। इन जिलों में पैदावार कम होने से राष्ट्रीय वृद्धि की दर नीची हो गई है और विकास के स्तर में विषमता और ज्यादा बढ़ गई है। यह एक ऐसा तत्त्व है जिसके कारण हमारे सघातक राज्यतंत्र के लिए सफलतापूर्वक कार्य करने में बाधक उलझने पैदा हो गई हैं।

7. कम और असमान वृद्धि होने का एक खास परिणाम यह हुआ है कि गरीबी के स्तर से नीचे का जीवनयापन करने वाले लोगों का अनुपात आज 1960-61 के मुकाबले ऊंचा है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि यह अनुपात 1968-69 से 1973-74 तक घटता गया था। किन्तु उसके बाद में तो यह हालत हर तरह से बिगड़ती गई है। समस्या की विशालता का अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1975-76 में अर्थ-व्यवस्था में इतनी भी क्षमता नहीं थी कि वह 12 करोड़ मेट्रिक टन अनाज के उत्पादन को भी खपा सके। क्रय-शक्ति के निम्नस्तर से कम-रोजगारी और बेरोजगारी की उस पुरानी हालत का पता चलता है जिसमें से भारी सख्या में भूमिहीन कामगार और छोटे तथा मीमा तक किसान गुजर रहे हैं। इस तथ्य से कि गरीबी के स्तर से नीचे का जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात आज 1960-61 के मुकाबले ऊंचा है, मेरे इस विश्वास की पुष्टि होती है कि हमारी आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों में मूलभूत परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगर स्थिति ज्यों की त्यों रही तो हमारे भविष्य के लिए उसके भीषण परिणाम होंगे। हमारे लोग जो हमारी नीतियों को दूसरी दिशा देने के लिए शोर-शराबा कर रहे हैं वे ठीक ही हैं। यह काम करने के लिए यह सरकार पूरी तरह बचनबद्ध है।

8. बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी की तकलीफों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जैसा कि सदन को मालूम है 1976-77 में थोक कीमतों का सूचक अंक लगभग 12 प्रतिशत बढ़ गया था। यह वृद्धि बहुत हद तक इस कारण हुई थी कि पिछले साल मुद्रा उपलब्धि में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई थी जिसके बचे हुए परिणाम आज भी अर्थव्यवस्था में अपना असर दिखा रहे हैं। हालांकि 1976-77 में प्रस्तुत विकारों से उत्पन्न एक कठिन मूल्य स्थिति हमें विरासत में मिली है फिर भी हम इस स्थिति को पूरी तरह काबू में लाने के लिए कृतसंकल्प हैं। उचित स्तर पर कीमतों को स्थिर रखने के लिए सकलपारित और आवश्यक साधन भी हमारे पास मौजूद हैं।

9. यह एक स्वतः सिद्ध तथ्य है कि ऐसे देश में जहां राष्ट्रीय आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग खेती से प्राप्त होता हो वहां अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर अवश्य ही कृषि क्षेत्र के उत्पादन से जुड़ी होगी। 1976-77 में अर्थव्यवस्था की जो घटिया स्थिति रही वह ज्यादातर खेती की पैदावार में कमी होने के कारण थी।

10. सातवें दशक के बाद वाले वर्षों में भारतीय कृषि ने अवश्य ही नई गतिशीलता के संकेत दिखाए थे। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी खेती संबंधी अर्थव्यवस्था पर आधुनिकीकरण की प्रेरणाओं का असर सीमित ही रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि आठवें दशक में कृषि उत्पादन में वृद्धि की दर सातवें दशक के मुकाबल ऊंची नहीं थी। गेहूँ ही सिर्फ़ ऐसी फसल है जिसकी पैदावार में तेजी से वृद्धि हुई है और इस में भी हाल के वर्षों में उत्पादकता की वृद्धि की दर बहुत धीमी पड़ गई है। चावल के मामले में अपारंपरिक राज्यों में बहुत बढ़िया लाभ मिला है लेकिन धान उगाने वाले बड़े राज्यों में पैदावार में प्रगति नहीं हुई है। दाल, तिलहन, कपास जैसी फसलों में गतिरोध की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यह बात स्पष्ट है कि यदि हमें कृषि के क्षेत्र में वृद्धि की दर को कम से कम 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ाना है तो अपनी खेती संबंधी अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए कुछ नए प्रेरक तत्व लाने होंगे।

11. हमारी विकास योजनाओं में अब तक सोच समझकर औद्योगीकरण पर जोर दिया गया था। और हमने अपने औद्योगिक ढांचे में विविधता लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी की है। फिर भी इस तथ्य के द्वारा जांच करने पर कि 1965 से औद्योगिक वृद्धि की दर 1956 से 1964 तक के वर्षों की 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की औसत दर की तुलना में, केवल 4 प्रतिशत रही है 1965 से प्रारम्भ होने वाले दशक को औद्योगीकरण में प्रगति का दशक मुश्किल से ही कह जा सकता है। जब औद्योगीकरण पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा हो उसी समय औद्योगिक वृद्धि की दर में गिरावट आए तो यह एक ऐसी घटना होगी जिसकी सावधानीपूर्वक जांच की जाने चाहिए। 1976-77 में औद्योगिक वृद्धि की दर 10 प्रतिशत तो अवश्य बढ़ी किंतु यह बताने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि ऐसा कई आकस्मिक परिस्थितियों के कारण हुआ जिसमें 1976-77 के अनुकूल परिणामों को अधिक हर्षप्रद प्रवृत्ति का सूचक नहीं माना जा सकता।

12. पर्याप्त वृद्धि की दर के कारण और उद्योग में पूँजी की प्रधानता बढ़ जाने की वजह से, भारत के औद्योगिक ढांचे में रोजगार के अवसरों का काफी तेजी से विस्तार करने की क्षमता नहीं रही है। इसके परिणामस्वरूप, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्ट्रारों में दर्ज बेरोजगार लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अत्यधिक परिरक्षित घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऊँची लागत के औद्योगिक ढांचे को, सीमित घरेलू बाजार की बाधयता के कारण, अपना विस्तार करने में अवश्य ही अधिकाधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

13. पिछले दो सालों में, जबकि भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा है, 1976-77 में आयात, 1975-76 की भरपूर फसल के कारण और उर्वरकों जैसी आवश्यक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो जाने की वजह से, सीमित रहा है। विदेशों से भेजी गई रकमों में तेजी से बहीतरी हो जान के कारण, भारत के भुगतान-शेष की ताकत बढ़ी है और हमारी प्रारक्षित निधियों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। फिर भी, हम नासमझ होंगे यदि हम इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखें कि हमारा भुगतान-शेष फसल की घटबढ़ जैसे आकस्मिक धक्कों के असर को सहन के लिए अब भी कमजोर है। इस समय हमारे जितना ख़ास भंडार है और जितनी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में मौजूद है, उससे हमें अवश्य ही अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने में पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक विकल्प प्राप्त है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित

निधियों को इस प्रकार काम में लाना होगा कि उनसे कीमतों को स्थिर बनाए रखने में सहायता मिले और वृद्धि की प्रक्रिया में तजी आए।

14 अब हमारा काम यह है कि हम एक ऐसी प्रभावोत्पादक कार्यनीति बनाए जिसके ज़रिए अपर्याप्त वृद्धि, कुचल डालने वाली गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलनों और बढ़ती हुई कीमतों की समस्याओं से निपटा जा सके। ये समस्याएँ एक दूसरी से संबंधित हैं और उन पर एक साथ कार्रवाई करनी होगी, हालांकि इन पर जो जोर दिया जाएगा उसकी मात्रा किसी खास अवधि में कम या ज्यादा हो सकती है।

15. यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हम जो भी कार्यनीति बनाए उसमें कृषि की प्रमुखता पर बल देना ही होगा। जिस देश में लगभग 80 प्रतिशत लोग देहाती इलाकों में रहते हैं, वहाँ गरीबी को हटाने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने और निर्मित वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार का विस्तार करने की किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कृषि की उत्पादकता को अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से बढ़ाना लगभग एक ऐसी शर्त है जिसे पहले पूरा करना होगा। कृषि की प्रमुखता का मतलब यह है कि कृषि की पूँजी निवेश मक्दमी ज़रूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि के महत्व को जानते हुए भी और ग्रामीण भारत की हालत को सुधारने की आवश्यकता को बार बार स्वीकार करने के बावजूद, पहले के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र को कुल निवेशयोग्य साधनों में से उचित हिस्सा नहीं मिला है। इस स्थिति को सही करने की ज़रूरत है। इस समय, सिंचाई की क्षमता लगभग 20 लाख हेक्टेयर की वार्षिक दर से बढ़ रही है। हमें अगले कुछ वर्षों में इस दर को दो गुना कर सकने के लिए एक योजना बनानी है। बड़े और मध्यम तथा छोटे सिंचाई-कार्यों को, पानी के दृष्टान्त उपयोग की राष्ट्रीय कार्यनीति के अंग के रूप में आयोजित और संपन्न करना होगा। इसी प्रकार, ग्रामीण आधारभूत ढाँचे के महत्वपूर्ण तत्वों, जैसे सड़कों, बाजारों और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था में पहले से अधिक पूँजी लगाने की तत्काल आवश्यकता है।

16. कृषि के विकास के कार्यक्रम को कृषि की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र के सभी घर-परिवारों को न्यूनाधिक रूप से संशोधित बनाने के उद्देश्य से भी तैयार करना होगा। इसके लिए साथ ही, मुर्गीपालन और डूँगरी उद्योग, मीन उद्योग, फार्म वन उद्योग आदि जैसे सहायक कार्यकलापों के विकास के लिए भी योजनाएँ बनानी होंगी। इसके लिए आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था तो करनी ही होगी, साथ ही ऐसे संगठनों का विकास भी करना होगा जो उपज को इकट्ठा करे, भंडार में रखे और बाजार में बेच, क्योंकि इन विभिन्न कार्यकलापों की सफलता के लिए बिक्री की कुशलतापूर्ण व्यवस्था अत्यावश्यक है। हमें देहाती इलाकों में रोजगार के काफी बड़े अवसर पैदा करने होंगे जिससे कि गाँव छोड़कर शहरों में आने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। यह उद्देश्य एकीकृत ग्रामीण विकास के क्षेत्र-केन्द्रित कार्यक्रम के माध्यम से भली भाँति प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें छोटे और सीमान्तिक किसानों और खतिहर मजदूरों की ज़रूरतों पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जाए।

17. अधिक साधनों की व्यवस्था कर देने मात्र से ही, भले ही वह कितनी ही महत्वपूर्ण हो, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इन साधनों को उपयोग में लाने के लिए संपूर्ण तंत्र को, प्रभावोत्पादकता में वृद्धि, करने के उद्देश्य से, पूरी तरह नया रूप देना होगा। इसके

लिए योजना बनाने और उम पर अमल करने वाले संगठन में परिवर्तन करने होंगे। कृषि की प्रोग्रेसिबि (टक्को तोजी) का सुधार करने के लिए अधिक गहन प्रयत्न करने होंगे और विचार कायी को भी बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। इसके लिए जन्दी से बाध, कुएं और नहर-नाले बनाने होंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम को तेजी से और कुशलतापूर्वक पूरा करना होगा, पानी और जमीन का पहले से अच्छा प्रबंध करना होगा, उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं की पूर्ति समय पर करने की पहले से अच्छी व्यवस्था करनी होगी, बीजों की अधिक सुव्यवस्थित पूर्ति करनी होगी और सग्रह करने और बेचने की बेडर सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। देश के कई हिस्सों में इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। जल्द ही इस बात की है कि ऐसे संगठनों को, अनेक साधनों के साथ, उन हिस्सों तक फैलाया जाए जो अभी इस काम में पीछे रह गए हैं। ऐसा प्रयत्न करने की जरूरत है जिससे उन अभिकरणों का पूरा कार्यापलट हो जाए जिनका इस समय कृषि विकास से सम्बन्ध है।

18. कृषि को प्रमुखता देने का यह मतलब नहीं है कि आधुनिक उद्योग के प्रति उदासीनता या उधेका दिखनाई जाए। इसका पूरा मतलब इतना ही है कि सरकारी क्षेत्र के लिए उपलब्ध निवेशयोग्य साधनों का पहले से बड़ा भाग कृषि विकास के लिए नियत किया जाए, और उद्यम औद्योगिक वृद्धि के लिए आवश्यक साधनों को अधिकाधिक मात्रा में बढ़ा जुटाएँ, जिसके लिए वे अधिक कुशलतापूर्ण कार्यचालन के द्वारा और कीमत निर्धारण को अधिक कारगर नीतियों के जरिये अपने खुद के आंतरिक साधनों को अधिक मात्रा में पैदा करें। सरकार भी उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, सीमेंट, बिजली और पैट्रोलियम जैसे उद्यमों के विकास पर, जिनका कृषि को उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान होता है, विशेष ध्यान देनी रहनी। भारतीय उद्योग में लागत के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए हमारा दरादा है कि अधिक उदार आयात नीति के जरिये, धीरे-धीरे अधिक प्रतियोगिता लागू की जाए। इसके अलावा, मौजूदा क्षमता का यथासंभव इष्टतम उपयोग करने के लिए अर्थोपाय ढूँढ़ने होंगे। साथ ही, नई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में हमें देरी नहीं होने देनी चाहिए जिसके कारण पूंजीगत लागत बढ़ जाया करती है। आमतौर पर यह महसूस नहीं किया जाता कि देरी हो जाने के कारण कितना ज्यादा खर्च बढ़ जाता है। जिन 18 परियोजनाओं ने 1976-77 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया था उनमें लागत वृद्धि के विश्लेषण से पता चलता है कि इन योजनाओं में निवेश की लागत बढ़कर 555 करोड़ रुपये हो गई जब कि मूल अनुमान 255 करोड़ रुपये के आस-पास था। इससे इस तथ्य के महत्व का पता चलता है कि परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करना कितना जरूरी है और देरी होने से समाज को कितना अधिक खर्च उठाना पड़ता है।

19. हमारे कुछ बड़े उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग आज गंभीर कठिनाई में हैं और उन्हें खासतौर से (कलपुर्जों) के बदलाव और आधुनिकीकरण की जरूरत है। इसलिए इन क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करनी होगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य आवधिक ऋणदाता संस्थाएँ इस प्रयोजन के लिए इस समय जो व्यवस्थाएँ कर रही हैं उन्हें आगे भी जारी रखना होगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयत्न करने होंगे कि ये उद्योग आंतरिक रूप से और ज्यादा साधन पैदा करें और ऐसी स्थिति में न पड़ जाए जिससे आखिरकार वे रुग्ण हो जाते हैं। मैं समझता हूँ, यह एक अच्छा विचार होगा कि अधिक कुशल मिलों के प्रबन्धकवर्ग को इस बात के लिए राजी कर लिया जाए कि वे एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में, कुछ रुग्ण एककों को अपने हाथ में ले लें

और सरकार द्वारा निर्धारित कौ जाने वाली शर्तों के अन्तर्गत उनकी तीमारदारी करके उन्हें फिर में म्वस्थ बना दे।

20. बिजली का अपेक्षाकृत अधिक तेजी से और ठीक समय पर विकास करना, तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए एक अन्यावश्यक शर्त है। यदि हम बिजली की बार-बार होने वाली भारी कमी का फिर में सामना नहीं करना चाहते तो मुझे पक्का विश्वास है कि अभी बिजली के आयोजन और विकास दोनों के बारे में बहुत कुछ करना बाकी है। अब बिजली को कृषि के लिए भी उतना ही जरूरी समझा जाता है जितना कि उद्योग के लिए, और बिजली की कमी अनाज के उत्पादन को भी, कपड़े के उत्पादन जितना ही, गड़बड़ा सकती है। इसलिए हम आने वाले वर्षों में बिजली के विस्तार की गति को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे।

21. एक क्षेत्र और भी है जिसमें आधुनिक उद्योग को और आगे विकसित करने की जरूरत है और वह क्षेत्र है निर्यात का। अब अनेक प्रकार की निर्मित वस्तुओं, खासतौर से, इजीप्टियरी सामान को विदेशी मंडियों में बेचने का अनुभव हमें प्राप्त हो गया है। चूंकि यही वह क्षेत्र है जिसमें विश्व व्यापार सबसे अधिक तेजी से बढ़ रहा है, हमें इस हलाके में भी आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हम अधिक क्षमता बनायें, उपयुक्त जानकारी प्राप्त करें और बिक्री की बेहतर तकनीकें भी अपनायें। जबकि मैं निर्यात-प्रधान वृद्धि को भारतीय परिस्थितियों में सफल हो सकने वाली बात नहीं मानता, तो भी यह आवश्यक है कि निर्यात उस दर से बढ़ते रहने चाहियें जिस दर से पिछले दो वर्षों में बढ़ते रहे हैं। आर्थिक प्रबन्ध के सबध में अधिक क्षमता प्राप्त करने के लिए यह बड़ोतरी आवश्यक है। सरकार स्थायी नीति के ऐसे ढांचे की व्यवस्था करने के लिए बचनबद्ध है जो कि निर्यात को लगातार बढ़ाने के लिए सहायक हो। साथ ही, हमने सत्यनिष्ठा के साथ यह संकल्प किया है कि हम तस्करी और उन समाज विरोधी तत्वों के साथ कड़ाई से निपटेंगे जो विदेशी मुद्रा का अवैध धन्धा करते हैं। सीमाव्यवस्था, विदेशों से भेजी जाने वाली रकमों से संबंधित हाल के आकड़ों से पता चलता है कि तस्करी का धन्धा बड़े पैमाने पर फिर से नहीं चल पाया लगता है। तथापि, हम इस मामले में सतर्क रहेंगे।

22. चूंकि बेरोजगारी हमारी एक सबसे ज्यादा दबाव डालने वाली समस्या है, इसलिए इसके हल के लिए सब से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि यह समस्या केवल औद्योगीकरण पर निर्भर रह कर ही नहीं सुलझाई जा सकती। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही बड़े पैमाने पर लाभपूर्ण रोजगार देने के लिए नई कार्य-नीतियां बनानी पड़ेंगी। कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप ही रोजगार की गुंजाइश बढ़ जाएगी। यह जानने योग्य दिलचस्प बात है कि जापान में प्रति एकड़ श्रम का प्रयोग, भारत में तदनुरूप स्तर की तुलना में चार गुना है। इससे यह संकेत मिलता है कि हमारी कृषि के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में नए रोजगार के अवसरों को पैदा करने की कितनी ज्यादा गुंजाइश है। अधिक सिंचाई, बेहतर कृषि पद्धतियों, दोहरी फसल, उर्वरकों के बढ़े हुए इस्तेमाल और खरपतवार की निराई से अवश्य ही अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि समय से पहले मशीनीकरण से कहीं इस प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कृषि की वृद्धि तेजी से होने से, मरम्मत, सेवार्थ, परिवहन आदि सहायक कार्यकलापों में रोजगार की वृद्धि होगी। साथ ही, ग्रामीण आधार-भूत ढांचे के विकास पर, खासतौर से, ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर अधिक ध्यान देना होगा। कृषि की उपज की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जा सकेगी यदि निकटतम मंडियों

के साथ हमारे गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी। स्थानीय उपज के परिष्करण की सुविधा प्रदान करने के लिए मोचविचार कर कदम उठाने होंगे। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रोजगार दिया जा सके। यदि बेरोजगारी की समस्या का कारगर हल हमें बूढ़ निकालना है तो गांधीजी के आत्मनिर्भर ग्रामोण समुदायों के विचार को ठोस रूप देना होगा।

23. लघु उद्योग के विकास से भी हम बेरोजगारी की समस्या को मुलद्वाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। लघु उद्योग बड़े उद्योग का छोटा रूपान्तर नहीं होना चाहिए बल्कि वह एक ऐसा उद्योग होना चाहिए जो उस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता हो जो हमारे फालतू श्रम और कुलभ पूंजी की परिस्थितियों के अनुकूल हो। यद्यपि समुचित प्रौद्योगिकी के बारे में काफी चर्चा होती रही है, किन्तु यह आश्चर्य की बात है कि हमने उसके विकास के लिए कितनी कम कोशिश की है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बैलगाड़ी परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है और आने वाले कई वर्षों तक रहेगी भी। तो भी अभी कुछ समय पहले ही हमने इसकी प्रभावोत्पादकता को सुधारने के बारे में सोचना शुरू किया है। दुर्भाग्य की बात है कि समुपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पर्याप्त साधनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम सदा सबसे आधुनिक प्रौद्योगिकी के पीछे पड़े रहते हैं, भले ही वह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत उपयोगी न रही हो। इस प्रवृत्ति को विपरीत दिशा में बदलना होगा।

24. किन्तु हमें इस क्षेत्र में शुरूआत करने के लिए समुचित प्रौद्योगिकी का इन्तजार करने की जरूरत नहीं है। हैडलूमो और पावरलूमो के अनुभव ने यह दिखला दिया है कि आधुनिक संगठन और बिजली के तरीकों से श्रमप्रधान उद्योग में जीवन का संचार कैसे हो सकता है। कुशलता के साथ अधिक रोजगार के अवसरों को पैदा करने के लिए दूसरे अनेक कुटीर और ग्राम उद्योगों में भी इसी तरीके से और काम करना चाहिए।

25. शहरी इलाकों में खासतौर से शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की समस्या कम गम्भीर नहीं है। मदन को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि हम इस समय एक ऐसी योजना के व्यौरों पर काम कर रहे हैं जो खासतौर से शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत, हम उन उद्यमी युवकों, जो सहायता पाने के पात्र समझे जायेंगे, ध्याज की अपेक्षाकृत आकर्षक दरों पर बैंकों से, 'बीज' धन और अन्य वित्त उपलब्ध करायेंगे।

26. आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर के लाभकारी प्रभाव जनसंख्या में वृद्धि होने से आसानी से व्यर्थ हो सकते हैं। इसलिए जनसंख्या के नियंत्रण को, जन साधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के हमारे कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाना होगा। दुर्भाग्यवश पिछले दो वर्षों की घटनाओं ने परिवार नियोजन के कार्यक्रम को ठीक उस समय एक जोरदार धक्का पहुंचाया जबकि वह पिछड़े हुए इलाकों में भी ग्रामतौर से स्वीकार किया जाने लगा था। हमारी आर्थिक प्रगति और कल्याण के लिए यह कार्यक्रम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों को छोटे परिवार का मानदण्ड स्वीकार करने के लिए तैयार करने के वास्ते लगातार सभी सम्भव प्रयत्न करने होंगे। इसलिए इस प्रयोजन के लिए जो भी निवेश जरूरी हो, बिना किसी हिचकिचाहट के, करना चाहिए। और चूंकि हमारा वृद्ध निश्चय है कि हम अपने उद्देश्यों को, दबाव की बजाय लोगों को समझा-बुझाकर ही प्राप्त करेंगे, इसलिए हमें इस विषय में पहले की अपेक्षा ज्यादा प्रयत्न करने होंगे और उन्हें लगातार जारी रखना होगा।

27. जिन कार्यक्रमों की मैंने चर्चा की है वे तभी सफल होंगे जबकि उनके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होंगे। जिन दूसरे देशों ने वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त कर ली है वे अपनी राष्ट्रीय आय का 30 प्रतिशत तक भाग लगा सके हैं क्योंकि उन्होंने काफी अधिक मात्रा में बचत की है। लेकिन भारत

का अनुभव दूसरी तरह का है। ऐच्छिक बचतें अपर्याप्त रही हैं। निर्मित धन और घाटे की वित्त व्यवस्था के जर्णिए घरेलू बचतों की दर को ऊँचा करने की कोशिशों से स्फीतिकारी दबाव तो बढ़ गया है परन्तु उनसे बचतों की दर को बढ़ाने में कोई सफलता नहीं मिली है। इसलिए अस्फीतिकारी तरीके से राष्ट्रीय बचतों की राशि को बढ़ाने के उपाय खोजने के लिए कुछ नए तरीके से विचार करना जरूरी है।

28. यह सन्देहपूर्ण है कि केवल कराधान से ही यह बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रत्यक्ष करों की ऊँची दरें उनके परिणामस्वरूप होने वाले अपवचन के कारण उत्पादन-विरोधी पाई गई है और किसी भी सूरत में, प्रत्यक्ष करों की परिधि में आने वाले लोगों की संख्या इतनी कम होती है कि राजस्व वसूली आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकती। अप्रत्यक्ष कराधान भी अपनी सीमा तक पहुँच गया लगता है।

29. करों के जर्णिए सरकार द्वारा जुटाए गए माधन पिछले वर्षों में लगातार बढ़ने गए हैं और इस समय कर-राजस्व राष्ट्रीय आय के अनुपात में 18.9 प्रतिशत तक ऊँचा है। किन्तु सरकारी बचत नहीं बढ़ी है। क्योंकि विकास-भिन्न व्यय, जैसे व्याज प्रभार, वेतन और मजदूरी, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, रक्षा व्यय और राज-महायना आदि, अनुपात में भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उद्यम मुख्यतः प्रबन्धकवर्ग की त्रुटियों और कीमतें तय करने की अनुचित नीतियों के कारण, अभी पिछले दिनों तक पर्याप्त कमाई नहीं कर रहे थे। यदि सरकारी बचत को बढ़ाना है और उससे बड़े निवेश में योगदान प्राप्त करना है तो उनमें से कुछ कमियों को दूर करना होगा।

30. वैयक्तिक बचत को अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है यदि सादगी और अधिक कारगर तरीके से बर्ती जाए। हमारे समाज में उपभोग में अधिकांश वृद्धि धनवान और सम्पन्न लोगों के जीवन-यापन के ऊँचे स्तर के प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण होती है। इस सबको प्रभाव शून्य करने के लिए उपभोग में अधिक समतावाद का पालन करना होगा। हमारी कर पद्धति को इस प्रकार नई दिशा प्रदान करनी होगी कि उससे आडवरपूर्ण जीवन-यापन को निरुत्साहित किया जाए और बचत की आदत को प्रोत्साहन मिले। किन्तु कराधान में सुधार कर देने मात्र में ही सादगी नहीं आ सकती। हमें उस प्रकार की जीवन-शैली के विरुद्ध जनमत जागृत करना होगा जो हमारे जैसे गरीब देश की कठोर आर्थिक वास्तविकताओं के सन्दर्भ में असंगत है।

31. कार्यभार संभालने के समय ही से सरकार कीमतों की स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा चिन्तित है। पिछले कुछ मप्ताहों में कीमतों में बराबर बढ़ने का जो रुख दिखाई दिया है वह कुछ तो पिछले साल के असन्तुलनों के संचित प्रभाव के कारण और कुछ मौसमी दबाव के कारण है जिससे वर्ष के इस भाग में नहीं बचा जा सकता। मैं यह वायदा नहीं कर सकता कि सरकार हर कीमत को स्थिर कर देगी क्योंकि माग या पूर्ति में घट-बढ़ होती रहती है और इस घट बढ़ को रोका नहीं जा सकता। फिर भी मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि आम उपभोग की बुनियादी चीजों के मामले में कीमतों में उचित स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमने कदम उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। स्थिर कीमतों पर सभी प्रकार की असली जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास अनाज का पर्याप्त भंडार है। वनस्पति तेलों के बारे में हमें कठिन स्थिति विरासत में मिली है। जैसा कि सदन को मालूम है, पिछले साल मृगफली के उत्पादन में अत्यन्त कमी हो जाने के कारण, वनस्पति तेलों की कीमतें काफी कुछ समय से बढ़ती रही हैं। दुर्भाग्यवश, मृगफली का तेल तत्काल विदेशों से नहीं मगाया जा सकता इसलिए इस तेल की पूर्ति के बारे में सीधे कार्रवाई करने की हमारी क्षमता सीमित है। किन्तु हमने दूसरे वनस्पति तेलों का पर्याप्त आयात करने का इन्तजाम कर लिया है। इससे खाना पकाने के काम आने

बाले तेलो की कीमत को स्थिर रखने में सहायता मिलनी चाहिए। बनावस्पति और सीधे इस्तेमाल के लिए साफ किए गए तोरिया के तेल के अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाने से मूंगफली के तेल की कीमतों पर जो दबाव पड़ रहा है वह अप्रत्यक्ष रूप से कम हो जाएगा हमारे पाम चीनी का पर्याप्त भंडार है उससे हम स्थिर कीमतों पर सभी उचित मांगों को पूरा कर सकते हैं। इस समय हम एक नई बहुतन्तुकीय नीति के व्योरो पर काम कर रहे हैं जो ग्राम आदमी की पहुँच के भीतर रहने वाली कीमतों पर अच्छा कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। यदि यह नीति सफल हो गई तो इससे एक और लाभ यह होगा कि भारत के इस सबसे बड़े उद्योग के सभी खंड फिर से स्वस्थ हो जायेंगे।

बजट अनुमान

32. अब मैं बजट अनुमानों की ओर आता हूँ। जो बजट पत्र आज मैं पेश कर रहा हूँ उनमें 1976-77 के संशोधित अनुमान जो अन्तरिम बजट में दिये गये थे, दोबारा दिए गए हैं, क्योंकि अधिकतर मामलों में वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

33. जहाँ तक चालू वर्ष के लिए बजट अनुमानों का संबंध है, आशा है कि कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर राजस्व 8,879 करोड़ रुपए होगा और इस प्रकार 1976-77 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 798 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस वृद्धि की राशि में से 101 करोड़ रुपए राज्य को करो में उनके हिस्से के रूप में मिलेंगे। संघीय उत्पाद शुल्कों से 4,550 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है जो पिछले साल के संशोधित अनुमानों से 373 करोड़ रुपए अधिक है, अनुमान है कि आय और निगम करो से 2,258 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी और इस प्रकार इस मद में 180 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। सीमा शुल्कों से 1,734 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है जो कि पिछले साल की तुलना में 243 करोड़ रुपए ज्यादा है।

34. बाजार ऋणों से गत वर्ष के 849 करोड़ रुपए की तुलना में, 1000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, सरकार विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में की जाने वाली निकासी के आधार पर 800 करोड़ रुपए उधार लेने का प्रस्ताव करती है।

35. अनुमान है कि मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी के लिए व्यवस्था करने के बाद 1,052 करोड़ रुपए की निवल विदेशी सहायता प्राप्त होगी, इसमें नए ऋणों के अंतर्गत मिलने वाले भुगतान भी शामिल हैं।

36. अन्य प्राप्तियों को हिसाब में लेने के बाद अनुमान है कि चालू वर्ष में कुल 15,366 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

37. अब मैं, संक्षेप में, आयोजना-भिन्न व्यय के अनुमानों का उल्लेख करना चाहूँगा। अन्तरिम बजट पेश करने समय मैंने यह बताया था कि वर्तमान सरकार सादगी पर जोर देगी और सब तरह के आडम्बर से अलग रहेगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को तथा सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों को यह कहा जाएगा कि वे स्तर में एकदम कफायत बरते। इसके बाद इस संबंध में सभी मंत्रालयों और विभागों को, कड़ाई से पालन करने के लिए ब्यौरेवार हिदायतें दे दी गई हैं। इन कफायती उपायों का पूरा असर तो सभी मालूम होगा जब इसके लिए की गई ब्यौरेवार कवायदें पूरी हो जायेंगी। इसके अलावा, अनावश्यक व्यय के कतिपय क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और बजट-पत्रों में इस कवायद के फलस्वरूप इन व्ययों में लगभग 130 करोड़ रुपए की कटौती दिखाई गई है।

33 रक्षा व्यय के लिए 2,752 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो अन्तरिम बजट में की गई व्यवस्था में 56 करोड़ रुपए कम है। खाद्य सहायता और सुरक्षित भंडार को ढोने के खर्च के लिए इस समय तो 460 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है लेकिन वर्ष के दौरान पैदा होने वाले रुखों के आधार पर इस पर फिर से विचार किया जाएगा।

39 राज्यों को करो में हिस्सा देने की अपनी योजना में, छठा वित्त आयोग ब्यौरे के अभाव में पाचवी आयोजना की अर्द्ध में राज्यों द्वारा लिए गए और बाटे गए ऋणों के खाते में उनकी निवल ब्याज सबंधी देनदारी को हिसाब में नहीं ले सका था। उस आयोग की सिफारिश के अनुसार, घाटे वाले राज्यों की निवल ब्याज सबंधी देनदारी का हिस्सा लगा लिया गया है और 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के सबंध में इस खाने में सबंधित राज्यों को अतिरिक्त सहायता अनुदान के लिए बजट में 72 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

40 केन्द्रीय सरकार के पेशन भोगियों ने मुझसे अनुरोध किया है कि जीवन निर्वाह के ऊंचे खर्च को ध्यान में रखते हुए उनकी पेशनों पर राहत की मात्रा को बढ़ाया जाए। जैसा कि मदन को मालूम है पड़ने भी समय समय पर राहत देने का उपाय किया गया है। मेरे विचार से इस समय यही उचित हाथा कि उन्हें क्रमिक दरों पर एक विशेष राहत प्रदान की जाए, इसके लिए राजकोष से प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।

41 अब मैं 1977-78 की वार्षिक आयोजना के परिष्यों की ओर आता हूँ। जैसा कि मैं पढ़ते बना दिया है, हमारा पक्का मन है कि आयोजनागत प्राथमिकताओं का व्यापक रूप से पुनः क्रम निर्धारण करके ही हम अपनी आर्थिक बुराईयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आयोजना का कार्यशक्ति का फिर से मूल्यांकन करना होगा। इसमें कृषि की प्रमुखता को मान्यता मिलनी चाहिए और ग्रामीण विकास तथा एक निश्चित समय-सीमा में बेरोजगारी के उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये ही वे काम हैं जिन्हें हमारा पुनर्गठित योजना आयोग अवश्य पूरा करेगा। फिर भी इसमें कुछ समय लग जाएगा। इस बीच सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह वांछित दिशा में आगे बढ़े। इस बजट का भी यही उद्देश्य है।

42 अब हमें जो थोड़ा सा समय मिला है। उसमें हमने विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करके 1977-78 की वार्षिक आयोजना के परिष्यों की तुरत समीक्षा की है और जहां तक संभव हुआ है, जनता पार्टी के घोषणापत्र में दी गई प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप हमारे विकास कार्यक्रमों को नई दिशा प्रदान करने की कोशिश की है। किन्तु हम कोरी पट्टी पर नहीं लिख रहे हैं। चालू योजनाओं को न तो छोड़ा जा सकता है और न ही उनकी गति को अनुचित रूप से धोमा किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से काफी वित्तीय हीनी होगी। राज्य सरकारों के साथ उनकी आयोजनाओं को अंतिम रूप देने के समय योजना आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, आदर करना होगा। इन बचनबद्धताओं के कारण, हमें अपनी विचारधारा के अनुसार आयोजना को नया रूप देने में अवश्य ही गंभीर रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए फेरबदल करने की गुंजाइश बहुत सीमित है। फिर भी अच्छी-खासी बचत कर ली गई है। अपेक्षाकृत नीची प्राथमिकता वाली योजनाओं को समुचित रूप से पुनः क्रमबद्ध किया गया है।

43. जनता को दिए गए वचनों का पालन करने हुए, हमने फिर से ढाली गई आयोजना में अब कृषि, सिंचाई बिजली, खादी और ग्रामोद्योग, कोशकीट-पालन, हाथ-करघा, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और टेलीफोन की सुविधाओं और अनेक ग्रामीण आधारभूत कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त परिष्यों की व्यवस्था की है। इन ग्रामीण कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ, जोड़ने वाली टिकाऊ

सड़को और गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था में सबधित योजनाएँ भी शामिल हैं। हमारा इरादा है कि ग्रामीण आधारभूत ढांच की सुविधाओं को विकसित करने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों पर अगले साल परीक्षण की और ज्यादा बढ़ाया जाए जिससे कि एक निश्चित अवधि में, मान लीजिए, पांच वर्ष में समूची ग्रामीण जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी की जा सकें। हमारा यह भी इरादा है कि राज्य सरकारों में परामर्श करके, गंदी वस्तुओं को साफ करने और शहरी क्षेत्रों को नया रूप देने के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाए और इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की गति को तेज करने के लिए अतिरिक्त साधनों की व्यवस्था की जाए।

44. 1977-78 के केन्द्रीय बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए और राज्यों तथा मधीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में सहायता देने के लिए 5,790 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। गत वर्ष इस कार्य के लिए 4,759 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। इस प्रकार विकास की गति को बनाए रखा जा रहा है।

45. केन्द्रीय बजट में आयोजन के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें 1812 करोड़ रुपए की वह राशि भी शामिल है जिसमें से राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाएगी और मधीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों की उप-आयोजना के लिए, उत्तरपूर्वी परिपद के लिए व्यवस्था की जाएगी और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को बिजली की योजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी। इस निर्धारित राशि में राज्यों को आयोजना के लिए दी जाने वाली विशेष अग्रिम सहायता का तत्व भी शामिल है जिसमें कि राज्य सिंचाई और बिजली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जरूरी परियोजनाओं में अपेक्षित स्तर पर निवेश करने के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था कर सके। बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए 3978 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकारी उपक्रमों के आन्तरिक और अन्य साधनों को शामिल करने हुए, केन्द्रीय आयोजना, 1976-77 के 4090 करोड़ रुपए के मुकाबले, 1977-78 में 4939 करोड़ रुपए की होगी। राज्यों और मधीय क्षेत्रों की आयोजनाएँ, कुल मिलाकर, 1976-77 के 3762 करोड़ रुपए के मुकाबले, 1977-78 में 5021 करोड़ रुपए की होगी। केन्द्र, राज्यों और मधीय राज्य क्षेत्रों की वार्षिक आयोजनाओं का कुल परिण्य, 1976-77 के 7852 करोड़ रुपए के मुकाबले, 1977-78 में 9960 करोड़ रुपए का होगा। यह 27 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है।

46. हम महसूस करते हैं कि अग्रदर्शी, गतिशील और विविधतापूर्ण कृषि की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि फसल उत्पादन, पशु धन और मुर्गी-पालन, मीन उद्योग और धन-रक्षण के एकीकृत विकास का उद्देश्य सामने रखा जाए। सहकारी आधार पर डेयरी उद्योग के विकास पर विशेष बल देने की जरूरत होगी जिससे दूध का उत्पादन करने वाले लोगों को बेहतर और उचित कीमतें मिल सकें। ओपरेशन फ्लड स्कीम के प्रथम चरण में सहायनीय प्रगति हुई है और अब हम इस स्कीम के दूसरे चरण का पूरा लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उत्पादनीय कृषि के आधुनिकीकरण पर आधारित होनी चाहिए। जिसमें निरंतर और यथासम्भव ऊँची वृद्धि की दर को प्राप्त करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्रौद्योगिकी का और ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। मौजूदा आयोजना की व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं को इस उद्देश्य से पुनः क्रमबद्ध किया गया है कि विकास से वंचित खाली जगहों का पता लगाया जा सके और मध्यम इलाकों को पहचाना जा सके जहाँ अधिक निवेश करने से कृषि की वृद्धि की गति और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करते हुए हमने (क) भविष्य में त्वरित विकास करने के लिए आधार के

रूरा में ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने, (ग) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने और (घ) पूर्ति तथा मांग के असंतुलनों को ठीक करने के लिए रूई, तेलहन और दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की जरूरतों को ध्यान में रखा है। हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों के विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना तैयार की जा रही है और इस प्रयोजन के लिए बजट अनुमानों में व्यवस्था कर दी गई है।

47 कृषि के उत्पादन का बढ़ाने की कुजी मिचार्ड के पास है। हालांकि पाचवी आयाजना में 58 लाख हैक्टेयर अनिर्विक्रित जमीन के लिए मिचार्ड की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है, फिर भी वित्तीय परिषद इस लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, परियोजनाओं को पर्याप्त श्रृंखला, बनाए रखने के उद्देश्य में, चालू आयोजना में नई मिचार्ड परियोजनाओं पर कार्रवाई शुरू करने की जरूरत पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। मिचार्ड की परियोजनाओं के आधुनिकीकरण पर भी और ज्यादा जोर देने की जरूरत होगी जिससे कि पानी को, जोकि एक दुर्लभ साधन है, सुरक्षित रखा जा सके। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम मिचार्ड की योजनाओं के लिए राज्यों को अभिन्न आयोजना सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करने है।

48 छोटी मिचार्ड के लिए आयोजना परिषद की अनुपूर्ति में लगभग 260 करोड़ रुपए की रणि कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम और अन्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दी जाएगी। पर सेटों को विज्ञान देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हमने 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जो संस्थाओं से प्राप्त बिल से काफी हद तक और बढ़ जाएगी।

49 कृषि और सहायक सेवाओं, बड़ी, मध्यम और छोटी मिचार्ड की परियोजनाओं तथा उर्वरकों और सहकारी संस्थाओं के लिए व्यवस्था एवं ग्रामीण इलाकों के लिए निर्धारित विज्ञान के क्षेत्रों के लिए, कुल मिला कर, 3024 करोड़ रुपए के आयोजना परिषद की व्यवस्था की गई है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह राशि केन्द्र, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के समूचे परिषद की 30.4 प्रतिशत बैठती है।

50 हालांकि राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों के विकास पर क्रमिक आयोजनाओं में युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त ध्यान दिया जाता रहा है, मगर अफसोस की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को उपेक्षा की जाती रही है। मैं समझता हूँ कि पहुँच सड़कों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र को पहल करनी चाहिए क्योंकि ये सड़कें ग्रामीण विकास के लिए आधारभूत ढांचा बनाने के किसी भी कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। इसलिए हम 20 करोड़ रुपए के परिषद के साथ इसकी शुरूआत करने का प्रस्ताव करने हैं। इसके लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा समुचित साधनों की अनुपूर्ति किए जाने पर, इन महत्वपूर्ण इलाकों में यह कार्यक्रम तेजी से बढ़ चलेगा। 'काम के लिए अनाज' की नई योजना का भी कल्पनाशीलता के साथ इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

51 आयोजना के तीन दशकों के बावजूद भी, अब भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि इस प्रयोजन के लिए साधन ढूँढने और कार्यक्रम कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार भी सक्रिय रूप में हस्तक्षेप करें और राज्यों के प्रयत्नों में योगदान दे।

इस अनुपूरक सहायता का उपयोग समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए और ऐसे गांवों का निर्धारण वस्तुपरक कसौटियों पर किया जाना चाहिए। हम तत्परता के साथ इसी वर्ष इस कार्यक्रम का शीर्गणेश करना चाहते हैं और इसके लिए मौजूदा परिस्थितियों के अलावा, 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करने का प्रस्ताव करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि में क्रमशः वृद्धि की जाएगी जिससे कि इस कार्यक्रम के लाभों को पांच साल की अवधि में सभी समस्याग्रस्त गांवों तक पहुंचाया जा सके। केन्द्र और राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की पूरी निगरानी रखनी होगी।

52. मैं यहां उन योजनाओं का भी उल्लेख करना चाहूंगा जो हरिजन, आदिवासियों और हमारे लोगों के दूसरे कम उन्नत वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इन योजनाओं को राज्यों की आयोजनाओं में स्थान मिला है। मैं इस संबंध में तैयार किए गए कार्यक्रमों और निर्धारित रकमों के बारे में सतुष्ट नहीं हूँ और इन मामलों में, प्राथमिकता के आधार पर, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से, इन कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से विचार-विमर्श करना चाहता हूँ।

53. बिजली के विकास के लिए केन्द्रीय आयोजना में 234 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इस व्यवस्था में मिर्गौली सुपर थर्मल स्टेशन के लिए 33 करोड़ रुपये, एक दूसरे सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर कार्रवाई शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपये, बिजली भेजने की अन्तर-राज्यीय लाइनों के लिए 17 करोड़ रुपये और परमाणु बिजली परियोजनाओं के लिए 52 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। राज्यों और मध्यम राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में, जहां बिजली के लिए अधिकांश व्यवस्था की गई है, 1676 करोड़ रुपये के परिस्थितियों की कल्पना की गई है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए 20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है जिससे बिजली तत्व का मुद्दा किया जाएगा और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एल. टी. कैपेसिटरो की व्यवस्था की जाएगी; इन दोनों कार्रवाइयों का उद्देश्य ऊर्जा की हानि को कम करना है।

54. ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तदनुसार पेट्रोलियम के लिए आयोजना में की गई व्यवस्था को बढ़ाकर, 1976-77 के 485 करोड़ रुपये के मुकाबले, 1977-78 में 677 करोड़ रुपये किया जा रहा है। इसमें से 451 करोड़ रुपये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तट पर तेल की खोज करने के उनके कार्यक्रम के लिए और तट से दूर समुद्र में खोज करने के कार्य की गति को तेज करने के लिए दिये जाएंगे। हमने हाल ही में बोम्बे हार्ड और बेसीन क्षेत्रों के तेल और प्राकृतिक गैस के विकास की योजना को मंजूर किया है। आशा है कि 1977-78 में, देश में कच्चे तेल का उत्पादन 113.1 लाख मेट्रिक टन तक हो जाएगा जबकि 1976-77 में 88.9 लाख मेट्रिक टन हुआ था।

55. तमिलनाडु में बिजली की कठिन स्थिति को देखते हुए, नेवेली लिगनाइट निगम के लिए 5 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई है जिससे 200 मेगावाट की क्षमता के एक नए लिगनाइट आधारित बिजली सयंत्र की स्थापना की जाएगी।

56. भिलाई और बोकारो कारखानों के विस्तार कार्यक्रमों को फिर से क्रमबद्ध करने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, हस्पात के लिए, इस बजट में, 1976-77 के 402 करोड़ रुपये के मुकाबले, 511 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

57. परिवहन और संचार के लिए बजट में 651 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है जिसमें से 302 करोड़ रुपए रेलवे के लिए होंगे जिसका आयोजना परिषद 480 करोड़ रुपए है। महानगरीय परिवहन परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से 86 करोड़ रुपए कलकत्ता की मास रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट के लिए है। बंबई में रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए छठे कोरिडोर प्रोजेक्ट के एक हिस्से को भी मंजूरी दे दी गई है।

58. ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डाक-तार सहित संचार संशुद्धि आयोजना में फेर बदल किया गया है। तदनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डाकघर खोलने के लिए और टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

59. हमारा यह विश्वास है कि खादी और ग्रामोद्योगों को अगर अच्छी तरह से सगठित किया जाए तो उनसे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सकता है। आयोजना में इन कार्यक्रमों के लिए 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था यह मानते हुए की गई है कि अगर जरूरत हुई तो और रकम भी मिल जाएगी, यह आशा की जाती है कि इन योजनाओं से लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

60. हथकरघे के लिए 20 करोड़ रुपए और कोशकीट पालन के लिए 4 करोड़ रुपए की और व्यवस्था की गई है जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। इन अतिरिक्त परिषदों की व्यवस्था इन ग्रामीणों और श्रमप्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से की गई है।

61. आयोजनागत और आयोजना-भिन्न दोनों खातों के व्यय को और कराधान के मौजूदा स्तरों पर अनुमानित प्राप्तियों को हिमाब में लेने के बाद, चालू वर्ष के बजट में 202 करोड़ रुपए का घाटा रहता है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 17th June, 1977

No. F 18(37)-B(D)/77.—The following is the text of speech delivered by the Finance Minister in the Lok Sabha on 17th June, 1977:—

Budget 1977-78

Speech of Minister of Finance

17th June, 1977

(PART "A")

Sir,

1. I rise to present the Budget for 1977-78, the first Budget to be presented by this the Janata Government.

2 The massive mandate that the people of India gave the Janata Party in March this year was not just a vote against authoritarianism. It was also a manifestation of our people's desire for a reorientation and a reshaping of our economic policies so as to bring about speedy elimination of poverty and destitution. In the last few weeks, our Government has taken several steps to dismantle the authoritarian and repressive structure erected during the dark days of Emergency. It is our firm belief that the open society we cherish will remain insecure unless we can move forward with courage and sincerity to banish poverty, ignorance and disease from this ancient land of ours. Our Party's election manifesto sets out a coherent economic strategy, laying emphasis on both bread and liberty. We seek to accelerate the pace of economic progress and to distribute its fruits equitably in a framework of democracy and individual freedom. Judging by historical precedents, this is no doubt a highly challenging task. The House can rest assured that there shall be no weakening of our solemn resolve to work for the fulfilment of promises we have made to our people.

3 The Budget of the Central Government is a major instrument for shaping the country's social and economic policies. Both because of shortage of time as also because of heavy commitments of expenditure on ongoing projects, it has not been possible for me to recast the entire fiscal structure in line with our declared priorities. Also, I did not have the benefit of consultations with the Planning Commission, which has been reconstituted only recently. Our Party's social and economic programme lays heavy emphasis on rural development, improvement of the lot of Harijans, Adivasis and other downtrodden sections, eradication of unemployment and expansion of social services including slum clearance. Most of the projects in these areas fall in the State Plans. For reasons which are well known to this House, it has not been practicable for me to consult State Governments and to induce them to reorient their development programmes in accordance with our priorities. Nevertheless, within the framework of the rather limited options open to me, I have endeavoured so to formulate my budget proposals that they reflect faithfully the philosophy, programmes and priorities of our election manifesto.

4 Before I outline the broad strategy that has been adopted, I would like to share with the House my thoughts on the current state and prospects of our economy. The Economic Survey has covered this ground fairly extensively, and I shall therefore be brief in my remarks on this subject.

5 The most fundamental problem of the Indian economy continues to be its inadequate rate of economic growth. In 1976-77, the rate of our economic growth was less than 2 per cent. In the seventies thus far, our growth rate has averaged about 3.5 per cent per annum, far too short of our Plan targets. And yet, while it would be wrong to assert that our country has not made significant progress since independence, the fact remains that even after twenty-five years of planning, we are unable to sustain an average growth rate of 5 per cent. Clearly, a fresh examination of our planning priorities and techniques is called for.

6 Another disturbing feature of the economic situation is the uneven distribution of growth, which has accentuated regional disparities in the level of development. While a number of States have recorded impressive growth rates during the last fifteen years, it is also a fact and a matter for serious concern that in this very period, nearly one-third of districts have recorded virtually no growth, or negative rates of growth, in output. The poor performance of these districts has both depressed the national growth rate and also led to a widening of disparities in the level of development, a phenomenon which has disturbing implications for the successful functioning of our federal polity.

7. A significant consequence of low and unevenly distributed growth has been that the proportion of people living below the poverty line is today higher than it was in 1960-61. The available data show that this proportion had tended to decline from 1968-69 to 1973-74, but in all probability the situation has deteriorated since then. The magnitude of the problem can be assessed from the fact that in 1975-76, the economy did not have the capacity to absorb the production of even 120 million tonnes of foodgrains. The low level of purchasing power is a reflection of the chronic state of underemployment and unemployment which is faced by large numbers of landless workers and small and marginal farmers. The fact that the proportion of people living below the poverty line today is higher than in 1960-61 strengthens me in my belief that there is need for a fundamental change in our economic policies and programmes. The *status quo* has disastrous implications for our future and our people are rightly clamouring

for a redirection of our policies. To this task, this Government is fully committed.

8 Rising prices have further accentuated the hardships faced by the common man. As the House knows, the wholesale price index went up by nearly 12 per cent in 1976-77. This was due, in a large measure, to an excessive increase in money supply last year, the lagged effects of which are still operating in the economy. Although we have inherited a difficult price situation caused by distortions introduced in 1976-77, we are determined to bring the situation fully under control. We have both the will as well as the necessary instruments to stabilise prices at a reasonable level.

9. It is a truism that in a country in which agriculture accounts for nearly 50 per cent. of national income, the overall growth rate of the economy is crucially linked to the performance of the agricultural sector. The poor performance of the economy in 1976-77 was largely because of the decline in our agricultural production.

10 In the late sixties, Indian agriculture did exhibit signs of a new dynamism. Unfortunately, the modernising impulses made only a limited impact on our agrarian economy. This is evident from the fact that the rate of growth of agricultural production in the 1970s was not higher than in the 1960s. Wheat is the only crop in respect of which there has been a rapid increase in production, but even there, the rate of growth of productivity has greatly slackened in recent years. In the case of rice, there have been impressive gains in non-traditional States, but in major rice growing States there has been no breakthrough in yields. Crops like pulses, vegetable oilseeds and raw cotton show a stagnant trend. Clearly, we have to introduce some new growth impulses into our agrarian economy, if we are to succeed in raising the agricultural growth rate to a minimum level of 4 per cent. per annum.

11. Our development plans had hitherto deliberately laid emphasis on industrialisation. And we have also made significant progress in diversifying our industrial structure. Yet, judging by the fact that the industrial growth rate since 1965 has averaged only 4 per cent. as compared with the average annual growth rate of 8 per cent. from 1956 to 1964, the decade since 1965 can hardly be described as a decade of progress in industrialisation. That an increasing emphasis on industrialisation should have coincided with a decline in the rate of industrial growth is a phenomenon which calls for careful examination. In 1976-77, industrial growth rate did increase to 10 per cent. However, there is ample evidence to suggest that this was due to a number of fortuitous circumstances so that the favourable results of 1976-77 cannot be taken as indicative of a more cheerful trend.

12 Both because of inadequate growth rate and growing capital intensity of industry, India's industrial structure has been unable to provide a fast enough expansion of employment opportunities. As a result, the number of unemployed people on the live registers of employment exchanges has risen sharply. A high cost industrial structure catering to a highly sheltered domestic market must necessarily find it increasingly difficult to expand in the face of the constraint of a limited home market.

13 In the last two years, while India's exports have increased rapidly, imports during 1976-77 were restrained both on account of the bumper harvest of 1975-76 and increased domestic production of such critical inputs as fertilisers. The rapid increase in inward remittances has given added strength to India's balance of payments and our reserves have gone up considerably. Nevertheless, we would be foolish if we did not take note of the fact that our balance of payment still remains vulnerable to the effects of sudden shocks, such as harvest fluctuations. The current level of food stocks and foreign exchange reserves do give us wider options in the management of the economy than ever before. Foreign exchange reserves will have to be so deployed as to assist in the maintenance of price stability, as also in accelerating the process of growth.

14 The task ahead is to devise an effective strategy for dealing with the problems of inadequate growth, crushing poverty, unemployment, growing regional imbalances and rising prices. These are all interrelated problems and have to be tackled simultaneously, though the emphasis laid at any given period of time may vary in degree.

15 It goes without saying that in any strategy we devise, the primacy of agriculture has to be emphasised. In a country in which nearly 80 per cent of the people live in rural areas, a faster increase in agricultural productivity is almost a precondition of any successful programme for removal of poverty, for enlarging employment opportunities, for stabilising prices of essential goods and for expanding the domestic market for manufactured goods. The primacy of agriculture implies that investment requirements of agriculture would be given the highest priority. In spite of the importance of agriculture and the repeated avowal of the need to improve the condition of rural India, the rural sector has in the past not received a fair share of total investible resources. This needs to be rectified. Currently, irrigation potential is growing at an annual rate of about 2 million hectares. We have to evolve a plan to be able to double this rate in the next few years. Both major and medium and minor irrigation works must be planned and executed as part of an optimal national strategy for water use. Similarly, there is an urgent need for stepping up investment in such crucial elements of rural infrastructure as roads, markets, and supply of pure drinking water.

16. The programme of agricultural development will have to be conceived not merely in terms of increase in agricultural productivity but also in terms of making all the households in the agricultural sector more or less viable. This will require, simultaneously, plans for development of ancillary activities like poultry and dairy farming, fisheries, farm forestry, etc. Not only will this involve the provision of necessary inputs but also the development of organisations which will collect, store and market the produce for efficient marketing is vital to the success of all these varied activities. We must generate large enough employment opportunities in rural areas so as to slow down migration to urban areas. This can best be achieved in the framework of an area-centred programme of integrated rural development, in which the needs of small and marginal farmers and agricultural labourers receive priority attention.

17 The provision of more resources, howsoever, vital, will not alone achieve the objective. The entire apparatus for utilising these resources will have to be completely revamped in order to improve their effectiveness. It will require changes in the organisation for both planning and implementation. It will need more intensive effort at improving agricultural technology and much greater extension effort. It will need speedier construction of dams, wells and channels, faster and efficient rural electrification, better water and land management, more timely supply of fertilisers and pesticides, a more organised supply of seeds and better storage and marketing facilities. Parts of the country have been able to achieve this. What is needed is the spreading of such organisation, together with requisite resources, to those lagging behind. The effort needed would call for a total transformation of the agencies which are presently connected with agricultural development.

18 Primacy of agriculture does not imply indifference towards, or neglect of, modern industry. All that it implies is that, in so far as a larger proportion of investible resources available to the public sector is diverted to agricultural development, resources for industrial growth will have to be found increasingly by enterprises themselves generating larger internal resources of their own through more efficient operation as well as more effective pricing policies. Government will also continue to pay particular attention to the development of industries such as fertilisers, pesticides, cement, power and petroleum which have an important bearing on agricultural productivity. In order to create greater cost consciousness in Indian industry, it is our intention to introduce, gradually, more competition by way of a more liberal import policy. In addition, ways and means will be found to make possible optimal use of capacity in existence. Simultaneously, in executing new projects, we must avoid delays which lead to escalation of capital costs. It is usually not realised how great is the cost of these delays. An analysis for cost escalations in 18 projects which had secured the approval in 1976-77 of the Public Investment Board shows that in these projects, investment costs had increased to Rs 555 crores as against the original estimate of about Rs 255 crores. This serves to emphasise the importance of timely execution of projects and the extremely high social cost of delay.

19 Some of our large industries, such as textiles, are today in serious trouble and are in particular need of replacement and modernisation. Therefore, adequate resources will have to be provided for investment in these sectors. The present arrangements which the Industrial Development Bank of India and the other term lending institutions have for this purpose will have to be continued.

Also, efforts have to be made to ensure that these industries generate more internal funds and, thus, do not face conditions which ultimately make them sick. I believe it might be a good idea, if the managements of more efficient mills were to be prevailed upon to take over, as an act of social responsibility, some of the sick units and nurse them back into sound health under conditions to be laid down by Government.

20. Faster and timely development of power is an essential condition of accelerated economic progress. I am convinced that much more remains to be done in respect of both power planning and development if we are not to have to face recurring severe shortages of power. Power is now recognised to be as essential to agriculture as to industry and shortages of power can disrupt the production of food as much as of cloth. We shall therefore make every effort to hasten the pace of expansion of power in the coming years.

21. There is another field, however, in which modern industry needs to be developed further and that is the field of exports. Experience has now been gained with regard to marketing a wide variety of manufactured goods, particularly engineering goods, in foreign markets. Since this is the field in which world trade is growing fastest, we should push ahead in this area. This means building up more capacity, acquiring suitable know-how and adopting even better marketing techniques. While I do not regard export-led growth as a viable proposition in Indian conditions, it is necessary that exports should continue to increase at the rate they have been growing in the past two years. Such an increase is essential for acquiring greater manoeuvrability with regard to economic management. Government is committed to provide a stable policy framework conducive to continued expansion of our exports. Simultaneously, it is our solemn resolve to deal firmly with smugglers and other antisocial elements indulging in illegal dealings in foreign exchange. Fortunately, judging by recent data on inward remittances, smuggling does not seem to have revived on any large scale. We shall, nevertheless, remain vigilant in this matter.

22. Since unemployment is one of our most pressing problems, the greatest attention needs to be given to its solution. By now, it is obvious that this problem cannot be solved through exclusive reliance on industrialisation. New strategies have, therefore, to be evolved to provide gainful employment on a large scale in the rural areas themselves. The accelerated growth of agricultural production will in itself increase the scope for employment in the rural areas. It is interesting to note that labour input per acre of land in Japan is four times the corresponding level in India. This is an indication of the scope for generating new employment opportunities in the process of modernising our agriculture. More irrigation, better cultural practices, double-cropping, increased use of fertilisers and weeding will certainly create more jobs, but it will have to be ensured that premature mechanisation does not affect this process adversely. Faster agricultural growth will offer greater scope for employment in such ancillary activities as repairing, servicing, transportation, etc. Simultaneously, greater attention will have to be paid to the development of rural infrastructure, particularly the construction of rural roads. Proper marketing of agricultural produce cannot take place if there is no adequate network of roads connecting our villages to the nearest marketing centres. Deliberate steps will also have to be taken to facilitate processing of local produce so as to provide more employment in rural areas. Gandhiji's idea of self-reliant rural communities will have to be given concrete shape if an effective solution is to be found to the problem of unemployment.

23. The development of small scale industry should also enable us to make a significant dent in the problem of unemployment. Such industry should not be a scaled-down version of large industry but should be one which uses technology which is appropriate to our conditions of surplus labour and scarce capital. Although there has been a great deal of talk of appropriate technology, it is surprising how little effort we have put into its development. For example, the bullock-cart remains and will remain for many years to come an important means of transport in rural areas. Yet, it is only very recently that we have started thinking about improving its effectiveness. Unfortunately, insufficient resources have been devoted to the development of appropriate technology. We have always gone after the most modern technology even though it may not necessarily have been the most efficient for us. This trend needs to be reversed.

24. We do not however have to wait for appropriate technology in order to make a beginning in this field. The experience of handlooms and powerlooms shows how modern organisation and marketing methods can breathe life into labour

intensive industry. More work along these lines should be tried with regard to number of cottage and village industries in order to combine greater employment with efficiency.

25 The problem of unemployment in urban areas, particularly among the educated persons, is no less serious. The House will be happy to know that we are now working on the details of a specific scheme designed to create opportunities for the educated unemployed. Under this scheme, we shall provide through the banking system "seed" money and other finance at relatively attractive rates of interest to enterprising young men considered eligible for assistance.

26. The beneficial effects of a high rate of economic growth can easily be neutralised by an increase in population. Therefore, population control has to be an integral part of our programme of raising the standard of living of the common man. Unfortunately, the events of the past two years have given the family planning programme a severe setback just when it was beginning to be generally accepted even in backward areas. This programme is so vital to our economic progress and well-being that all possible efforts must be made in a sustained way to persuade people to accept the small family norm. Any investment, therefore, that is necessary for this purpose should be undertaken without any hesitation. And because it is our firm determination to achieve our objectives through persuasion rather than coercion, the effort that will have to be put in will have to be greater and more sustained.

27 The success of the programmes I have been talking about depends upon adequate resources being available. Other countries which have achieved high rates of growth have been able to invest as much as 30 per cent of national income because of their high volume of savings. The Indian experience has been otherwise. Voluntary savings have been inadequate. Attempts to push up the rate of domestic savings through created money and deficit financing have accentuated inflationary pressures but have not succeeded in raising the savings rate. Thus, some fresh thinking is necessary regarding the means of enlarging the pool of national savings in a non-inflationary manner.

28. It is doubtful if taxation can achieve such an increase. High direct tax rates have been found to be counter-productive because of the evasion that ensues, and, in any case, the number of people who fall in the direct tax net is so small that revenue realisation cannot match requirements. Indirect taxation seems also to have reached its limit.

29 Resource mobilisation by the Government through taxes has increased continuously over the years and at present tax revenue as percentage of national income is as high as 18.9. But public saving has not gone up because non-developmental expenditure such as interest charges, salaries and wages, dearness allowance to employees, defence expenditure and subsidies etc., have gone up more than proportionately. In addition, public sector enterprises have not been earning, until recently adequate return chiefly because of deficiencies of management and improper pricing policies. Some of those shortcomings will have to be removed if public saving is to increase and contribute to larger investment.

30 Individual saving can be promoted better if austerity is practised much more effectively. A large part of the increase in consumption arises from the demonstration effect of the high standard of living of the wealthy and the well-to-do in our society. To neutralise all this, greater egalitarianism in consumption needs to be practised. Our tax system has to be so reoriented as to discourage ostentatious living and promote the habit of savings. However, austerity cannot be ushered in merely through tax reform. We must arouse public opinion against a life style inconsistent with the harsh economic realities of a poor country such as ours.

31. Government has been greatly concerned about the price situation ever since it came into office. The persistence of the rising tendency in prices witnessed during the last few weeks has been due, partly to the cumulative effect of imbalances introduced last year and partly due to the seasonal pressure which is unavoidable during this part of the year. I cannot hold out the promise that Government will be able to stabilise every single price in face of fluctuations in demand or supply which are inevitable. However, I can assure the House that we have taken steps, and will continue to do so, to ensure reasonable price stability in respect of basic articles of mass consumption. We have enough stocks of food

grains to meet all genuine requirements at stable prices. We have inherited a difficult situation regarding vegetable oils. As the House knows, because of a steep fall in production of groundnuts last year prices of vegetable oils have been rising for quite some time. Unfortunately, groundnut oil cannot be readily imported so that our ability to operate directly on the supply of this oil is rather limited. However, we have arranged for adequate imports of other vegetable oils. These should help to stabilise the price of cooking media. Increased availability of vanaspathi and refined rapeseed oil meant for direct consumption would indirectly ease pressure on prices of groundnut oil. We have adequate stocks of sugar to enable us to meet all reasonable demands at stable prices. We are now working on the details of a new multifibre policy designed to make available quality cloth at prices within the reach of the common man. Such a policy, if successful, would have the additional advantage of restoring to health all segments of India's largest industry.

BUDGET ESTIMATES

32 I now turn to the Budget Estimates. The documents which I am presenting today repeat the Revised Estimates for 1976-77 as given in the Interim Budget, as the actuals are not yet available in most cases.

33 As regards the Budget Estimates for the current year, gross tax revenues at existing rates of taxation are estimated at Rs. 8879 crores, showing an increase of Rs. 793 crores over the Revised Estimates for 1976-77. Of the increase, Rs. 101 crores will accrue to the States as their share of taxes. While Union Excise Duties are expected to yield Rs. 4550 crores, showing an increase of Rs. 373 crores over the Revised Estimates for last year, receipts from Income and Corporation taxes are estimated at Rs. 2258 crores, an increase of Rs. 180 crores. Customs receipts at Rs. 1734 crores will be higher by Rs. 243 crores as compared to last year.

34. Market loans are expected to yield Rs. 1000 crores as compared to Rs. 849 crores in the previous year. Besides, Government propose to borrow Rs. 800 crores against drawal of foreign exchange reserves.

35. Net external assistance, after providing for repayments and interest payments, is estimated at Rs. 1052 crores, including disbursements against new credits.

36 Taking other receipts into account total receipts in the current year are estimated at Rs. 15366 crores.

37 I may now make a brief mention of the estimates of non-Plan expenditure. While presenting the Interim Budget, I indicated that all Ministries and Departments of Government and public sector agencies will be asked to observe the utmost economy in expenditure, keeping in view the present Government's emphasis on austerity and avoidance of all forms of ostentation. Detailed instructions have since been issued in this regard for strict compliance by all Ministries and Departments. The full impact of the economy measures will be known only after the detailed exercises have been completed. Separately certain areas of non-essential expenditure have already been identified and the Budget documents reflect a reduction of about Rs. 130 crores in these expenditures as a result of this exercise.

38 The provision for Defence expenditure is Rs. 2752 crores, Rs. 56 crores less than the provision made in the Interim Budget. The provision for food subsidy and carrying costs of buffer stocks has been for the present, retained at Rs. 460 crores, but it will be reviewed on the basis of emerging trends during the course of the year.

39 In its scheme of devolution, the Sixth Finance Commission could not take into account the net interest liability of States on account of loans raised and disbursed by them during the Fifth Plan period for want of details. As recommended by that Commission, the net interest liability of the deficit States has been computed and a provision of Rs. 72 crores has been made in the Budget for disbursement of additional grant-in-aid to the States concerned on this account, in relation to the three years ending on 31st March, 1977.

40 I have received requests from Central Government pensioners for increase in the quantum of relief on their pensions in view of the high cost of living. As the House is aware, a measure of relief has been afforded from time to time in the past. I feel it would be only fair at this stage to grant a special relief at graded rates to them; this will cost the exchequer Rs. 10 crores annually.

41. I now turn to the outlays on the Annual Plan for 1977-78. As I have already indicated, we are firmly of the view that our economic ills can be overcome only through a comprehensive reordering of Plan priorities. The Plan strategy has to be reappraised. It should recognise the primacy of agriculture and accord overriding priority to rural development and eradication of unemployment within a time frame. These are the tasks to which our reconstituted Planning Commission will no doubt address itself. That, however, will take some time. In the meanwhile it is necessary for the Government to move in the desired direction. That is what this Budget seeks to do.

42. Within the short time available to us, we have therefore made a quick review in consultation with various Ministries of the outlays in the Annual Plan for 1977-78, and tried to impart, to the extent possible, a new direction to our development programmes in line with the priorities and objectives set out in the Manifesto of the Janata Party. We are, however, not writing on a clean slate. Schemes in progress cannot be abandoned, nor even slowed down unduly, without considerable financial loss. The commitments made to State Governments in regard to Central assistance for their Plans have also to be honoured subject to the conditions stipulated by the Planning Commission at the time of the finalisation of their Plans. These commitments do impose serious limitations in refashioning the Plan according to our thinking. The room for manoeuvrability is thus limited. Even so, appreciable savings have been effected. Schemes of relatively low priority have been suitably rephased.

43. True to the promises made to the people, in the recast Plan, we have now provided for additional outlays for agriculture, irrigation, power, khadi and village industries, sericulture, handlooms, postal and telephone facilities in rural areas and wide ranging rural infrastructure programmes covering, among other things, such schemes as durable link roads and rural drinking water supply. It is our intention to step up further the outlays next year on programmes designed to develop rural infrastructure facilities so that over a period of, say, five years the basic needs of the entire rural population could be met. It is also our intention to review the programmes of slum clearance and urban renewal in consultation with the States and to provide additional resources for accelerating the pace of execution of these programmes.

44. The allocations from the Central Budget in 1977-78 for the Central Plan and assistance towards Plans of States and Union territories will be Rs 5790 crores. The corresponding figure for the previous year was Rs 4759 crores. The tempo of development is thus being maintained.

45. The provision for the Plan in the Central Budget is inclusive of Rs 1812 crores on account of Central assistance for State Plans and provisions for Union territories Plans, the sub-plan of the Hills and Tribal Areas, the North-Eastern Council, and assistance to the Rural Electrification Corporation for power schemes. This allocation also includes an element of special advance Plan assistance to States to provide them adequate resources for the required level of investment in important projects in the core sectors of irrigation and power. A provision of Rs 3978 crores has been made in the Budget towards Central Plan. Inclusive of the internal and other resources of public undertakings, the Central Plan will be of the order of Rs 4939 crores in 1977-78 as against Rs 4090 crores in 1976-77. The State and Union territories Plans together will be of the order of Rs 5021 crores, as against Rs 3762 crores in 1976-77. The total outlay on the annual Plans of the Centre, States and Union territories for 1977-78 will be Rs 9960 crores, as against Rs 7852 crores in 1976-77. This represents an increase of 27 per cent.

46. We feel that for building a forward looking, dynamic and diversified agricultural economy, it is necessary to aim at integrated development of crop production, livestock and poultry, fisheries and forestry. Special emphasis will need to be laid on development of dairy industry on a cooperative basis with a view to enabling milk producers to get better and fair prices. Creditable progress has been made in the first phase of Operation Flood Scheme and we must now get moving to take the full advantage of Operation Flood Phase II. The production policy should be based on modernisation of agriculture in which technology should, by far, be the most crucial input to make a sustained and high growth rate possible. The existing Plan provisions and priorities have been rephased with a view to locating gaps in development and identifying the potential areas where increased investments could bring about further acceleration of the pace of agricultural growth. In this exercise we have kept in view the need for (a) strengthening

rural infrastructure as a basis for future accelerated development, (b) generation of employment in rural areas, (c) special attention to the needs of the weaker sections of the society, and (d) giving a fillip to the production of cotton, oil seeds and pulses so as to correct the supply and demand imbalances. A pilot project for desert development in Haryana, Gujarat and Rajasthan is being evolved and provision has been made for this purpose in the Budget Estimates.

47. Irrigation holds the key to increased agricultural production. Though the Fifth Plan envisages a target of 5.8 million hectares to be brought under irrigation, the financial outlays do not match the target. Further, the need for initiating action in the current Plan on new irrigation projects, so as to have an adequate pipeline of projects has been neglected. Greater emphasis will also have to be laid on modernisation of irrigation projects so as to conserve water, which is a scarce resource. Keeping all these ends in view, we propose to provide Rs 100 crores as advance Plan assistance to States for irrigation projects.

48. The Plan outlays for minor irrigation will be supplemented to the extent of about Rs 260 crores from the Agricultural Refinance and Development Corporation, and other lending institutions. Under the programme of rural electrification for energising the pump sets, we have made a provision of Rs 175 crores which will also be augmented to a significant extent by institutional finance.

49. The total Plan outlay on agriculture and allied services, major, medium and minor irrigation projects and fertilisers, together with provisions for cooperatives and power sectors attributable to rural areas, works out to Rs 3024 crores. The House will be glad to know that this constitutes 30.4 per cent of the aggregate outlay of the Central, State and Union territories Plans.

50. While the development of National and State highways has received reasonably adequate attention in successive Plans, the needs of rural areas have been sadly neglected. I feel that the Centre should take the initiative in promoting the construction of approach roads which constitute an essential ingredient of any programme for building up the infrastructure for rural development. We therefore propose to make a beginning with an outlay of Rs. 20 crores which, suitably supplemented with the resources of the State Governments and local bodies, will accelerate the programme in this vital area. The new scheme of 'grain for work' could also be utilised imaginatively for this purpose.

51. Despite three decades of planning, there are still a large number of villages which suffer very acute scarcity of drinking water. While the responsibility for finding resources and execution of the programmes for this purpose is that of the State Governments, I feel that the Central Government should also intervene actively and supplement the efforts of the States. Such supplementary assistance should be directed towards provision of drinking water facilities in problem villages to be identified with reference to objective criteria. We propose to make an earnest start in the current year with an additional provision of Rs. 40 crores over and above the existing outlays for this programme. Progressively, the allocations for this programme would be stepped up so as to carry the benefits of the programme to all the problem villages over a period of five years. The programme will have to be closely monitored at the Central as well as the State level.

52. I would also like to refer here to schemes for the welfare of Harijans, Adivasis and other less advanced sections of our people. As I have said earlier, these find a place largely in State Plans. I am not satisfied with the programmes and allocations in respect of them and it is my intention to take up these matters on a priority basis with State Governments and Central Ministries concerned so as to add to the effectiveness of these programmes.

53. A sum of Rs. 234 crores has been provided in the Central Plan for power development. This includes Rs. 33 crores for Singrauli Super Thermal Station, Rs. 1 crore for initiating action on a second Super Thermal Power Station, Rs. 17 crores for inter-State transmission lines, and Rs. 52 crores for nuclear power projects. The State and Union territories Plans, which account for the bulk of the provision for power, envisage an outlay of Rs. 1676 crores. An additional sum of Rs. 20 crores is being provided to the Rural Electrification Corporation for systems improvement and for providing I.T. Capacitors for rural consumers, both designed to minimise loss of energy.

54. Self-sufficiency in energy has assumed critical importance. The provision in the Plan for petroleum is being accordingly stepped up from Rs. 485 crores in 1976-77 to Rs. 677 crores in 1977-78. Of this Rs. 451 crores will be provided

to the Oil and Natural Gas Commission for their on-shore exploration programme and for accelerating the pace of off-shore exploration. We have recently cleared the scheme for development of oil and natural gas resources of Bombay High and Bassin fields. Indigenous production of crude oil is expected to reach 11.31 million tonnes in 1977-78 as compared with 8.89 million tonnes in 1976-77.

55 Having regard to the difficult power situation of Tamil Nadu, a special provision of Rs. 5 crores has been made for Neyveli Lignite Corporation for a new lignite based power plant with a capacity of 200 MW.

56 After taking into account the feasibility of rephasing the expansion programmes of the Bhilai and Bokaro complexes, a budgetary allocation of Rs. 511 crores has been made for steel as compared with Rs. 402 crores in 1976-77.

57 The budgetary allocation for transport and communications will be Rs. 651 crores, of which Rs. 302 crores will be for the Railways which have a Plan outlay of Rs. 480 crores. A provision of Rs. 10 crores has been made for metropolitan transport projects, of which Rs. 8.6 crores is for the Mass Rapid Transit Project of Calcutta. A part of the Sixth Corridor Project for rapid mass transit system in Bombay has also been sanctioned.

58 The Plan for communications, including Posts and Telegraphs, has been modified to take into account the priority requirements of rural areas. Accordingly, an additional outlay of Rs. 10 crores has been provided for opening more post offices and extension of telephone and telegraph facilities in rural areas.

59 It is our belief that khadi and village industries, if they are properly organised and supported, are capable of generating employment on a large scale. A provision of Rs. 35 crores has been made for these programmes in the Plan, with the understanding that more funds will be allocated, if required. It is expected that the schemes in view will provide employment for about 25 lakh persons.

60 An outlay of Rs. 20 crores is provided for handloom and Rs. 4 crores for sericulture which is a substantial step up over last year. These additional outlays have been made with a view to giving a fillip to these rural and labour intensive industries.

61 Taking into account the expenditure both on Plan and non-Plan counts and the estimated receipts at existing levels of taxation, the Budget for the current year shows a deficit of Rs. 202 crores.

बजट 1977-78

विस मंत्री का भाषण

17 जून, 1977

(भाग "ख")

प्रत्यक्ष कर

62 अब मैं इस घाटे को सम्भव सीमा तक पूरा करने के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव पेश करना हूँ।

63 प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित जिन प्रस्तावों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ उनका उद्देश्य कम्पनियों की बचतों को बढ़ाना, उत्पादक निवेशों में और धनराशि लगाना, औद्योगिक वृद्धि की गति को तेज करना और साथ ही प्रत्यक्ष करों की पुनर्वितरणकारी भूमिका को जो कि मेरे विचार से प्रत्यक्ष करों को अवश्य निभानी चाहिए, सुदृढ़ करना है।

64 जहाँ तक अप्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, मैंने इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास किया है कि मेरे प्रस्तावों का जीवनयापन की आवश्यक वस्तुओं के साथ

टकराव न हो। कुछ मुपाव क्षेत्रों को राहत देने हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के टैरिफ ढांचे को सामान्य रूप से सरल और युक्तिमंगत बनाने हुए, प्रमुख रूप से मैंने अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तुओं अथवा ऐश-आराम की वस्तुओं से साधन जुटाने का प्रयास किया है।

65 जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में किए गए एक वायदे को पूरा करने के इरादे से मैं इस व्यवस्था का प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि जिन व्यक्तियों (इंडिविजुअल्स) तथा हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों की कराधान-योग्य आय 10,000 रुपए से ज्यादा न हो, उन्हें कोई आयकर न देना पड़ेगा। किन्तु राजस्व के इस बलिदान को न्यूनतम सीमा पर रखने के लिए, आय का वह खंड जिस पर आयकर नहीं लगता, 8,000 रुपए तक ही कायम रखा जा रहा है। अतः जिन मामलों में कराधान योग्य आयकर 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी, उन मामलों में 8,000 रुपए से ऊपर की आय पर उसी तरह से कर लगाया जाएगा जैसे अब लगाया जाता है, किन्तु जिन मामलों में, कराधान-योग्य आय 10,000 रुपये से थोड़ी-सी ज्यादा हो, उनमें उसी हिसाब से मामूली राहत भी दी जा सकेगी।

66 मैं आय कर की आधारीक दरों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। फिर भी अतिरिक्त साधन जुटाने की महती आवश्यकता को देखते हुए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कम्पनियों को छोड़कर, करदाताओं के समस्त वर्गों के सम्बन्ध में आयकर पर अधिभार की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए। अधिभार की दर में वृद्धि हो जाने से, वैयक्तिक आयकर की अधिकतम सीमान्तिक दर, 69 प्रतिशत हो जाएगी जबकि इस समय यह दर 66 प्रतिशत है।

67 मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि 1976 के बजट में धन कर की दरों में, अनुचित सीमा तक कमी कर दी गई थी। यदि धन कर के असली उद्देश्य को पूरा करना है तो धन कर की व्यवस्था इस तरीके से की जानी चाहिए कि यह कर न तो दुखदायी हो और न ही उत्पादन-विरोधी, बल्कि व्यक्तियों के हाथों में अत्यधिक धन संचय पर इसका असर जरूर पड़े। मामले के इस पक्ष को देखते हुए, धन कर की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। पहले 2.5 लाख रुपये के निवल धन पर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत की मौजूदा दर, बिना किसी परिवर्तन के, कायम रखी जाएगी लेकिन हमसे ऊपर के खण्डों के लिए, मौजूदा दरों में $\frac{1}{4}$ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी, और सब में ऊंचे खण्ड के सम्बन्ध में अर्थात् 15 लाख रुपए में ऊपर के उच्चतम खण्ड के सम्बन्ध में, कर की नई दर साढ़े तीन प्रतिशत होगी, यानी मौजूदा दर के ऊपर एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के सम्बन्ध में, जिनमें एक या एक से अधिक सदस्यों के पास 1 लाख रुपए से ज्यादा का निवल धन हो, लागू होने वाली दरों में भी तदनु रूप परिवर्तन किए जायेंगे। नई दर अनुसूची चारू कर-निर्धारण वर्ष में लागू होगी और दर अनुसूची में जो परिवर्तन गत वर्ष किए गए थे, उनको अधिकांश कर देंगी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप 1977-78 में लगभग 10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

68 जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, सरकार ने अनिवार्य जमा योजना, जहां तक कि यह अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर लागू होती है, 6 मई 1977 से समाप्त कर दी है। किन्तु अर्थ-व्यवस्था की स्थिति को तथा मुद्रा-स्फीतिकारी मौजूदा दबावों को ध्यान में रखते हुए मैं आयकरदाताओं के सम्बन्ध में अनिवार्य जमा योजना को और दो वर्ष के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

69. औद्योगिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मैं निवेश छूट योजना के क्षेत्र को, जिसे पिछले वर्ष शुरू किया गया था, और व्यापक बनाना वाछनी समझता हूँ। दुर्भाग्य से उस योजना में कोई भी सुपरिभाषित और स्पष्ट मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है जिसके अनुसार ऐसे उद्योगधन्धों का चुनाव किया जा सके जिनको इस रिआयत का लाभ दिया जाना चाहिए। इस लिए रिआयत पाने के दावेदारों को यह समझाना कठिन हो गया था कि यह लाभ कुछ उद्योगों को ही क्यों दिया गया, जबकि दूसरों को नहीं दिया गया। चूंकि निवेश की वित्त-व्यवस्था करने के उद्देश्य में आन्तरिक साधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं यह ठीक समझता हूँ कि उद्योगधन्धों को छोड़कर, जो निर्दिष्ट किस्म की कम प्राथमिकता वाली वस्तुओं, जैसे मिगरेटों, श्रृंगार सामग्री, तथा मकूथसारयुक्त पेय पदार्थों के निर्माण में लगे हैं जेथे सभी उद्योगधन्धों में निवेश छूट योजना लागू कर दी जाए। अर्थ-व्यवस्था के लिए यह उपाय बहुत लाभदायक सिद्ध होगा।

70. वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मैं उन लोगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करना चाहता हूँ, जो अपने ही देश में विकसित तकनीकी जानकारी का उपयोग करते हैं। तदनुसार प्रस्ताव किया जाता है कि सरकारी प्रयोगशालाओं, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा विश्वविद्यालयों में विकसित तकनीकी ज्ञान के अनुसार बनाई जाने वाली किसी चीज के निर्माण के लिए जो भी मशीनें या मयंत्र स्थापित किए जाएं उनके सम्बन्ध में 35 प्रतिशत की अपेक्षाकृत ऊँची दर पर निवेश छूट दी जाए।

71. उद्योगधन्धों का अधिकतम विस्तार करने के उद्देश्य को सामने रखते हुए मैं अल्पजन-धारित औद्योगिक कम्पनियों को इस बात के लिए विवश करने में कोई लाभ नहीं समझता कि वे अपने निवल लाभ के काफी ज्यादा प्रतिशत अंश को लभांश के तौर पर वितरित करें। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रकार की कम्पनियों को लभांश के अनिवार्य वितरण की अपेक्षा से छूट दे दी जाए। मैं यह गहन अन्य किस्म की सभी दूसरी अल्पजनधारित कम्पनियों के सम्बन्ध में नहीं देना चाहता।

72. मेरा विश्वास है कि पूजोगत लाभों पर कर लगाने की मौजूदा व्यवस्था में निवेश योग्य साधनों की पर्याप्त गतिशीलता के मार्ग में रुकावट पैदा होती है और इससे कम प्राथमिकता वाली परिसम्पत्तियों में ही पूँजी निवेश किये जाने की प्रवृत्ति को बल मिलता है। इस दृष्टि से, मैं पूँजीगत लाभों के कराधान की वर्तमान योजना में कुछ परिवर्तन किए जाने का सुझाव देता हूँ।

(क) इस समय केवल उन्हीं पूँजीगत लाभों पर कर सबधी रिआयते मिल सकती है जो ऐसी पूँजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से हुए हों जो करदाता के कब्जे में 60 महीने से अधिक की अवधि तक के लिए रही हैं। गतिशीलता सुधार करने की दृष्टि से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कब्जे की अवधि कम करके 36 महीने कर दी जाए।

(ख) जो पूँजीगत परिसम्पत्ति पहली जनवरी 1954 से पहले अर्जित कर ली गई थी उस के सम्बन्ध में करदाता उस परिसम्पत्ति की प्राप्ति की वास्तविक लागत के बजाय उसके पहली जनवरी 1954 के उचित बाजार मूल्य को भी अपना सकता है। 23 वर्ष से भी पहले की किसी तारीख की किसी पूँजीगत परिसम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य क्या था इसका निर्धारण करने में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ

माती है। इसके अलावा, एक लम्बे अर्से तक धारित परिसम्पत्ति के अन्तरण से जो पूजीगत लाभ प्राप्त होता है वह ऐसी दुनिया में जहाँ पर मुद्रास्फीति बराबर बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, बड़ी हद तक अमूर्ण ही है। इसलिए कुल मिलाकर मुझे यही वाछनीय लगता है कि कल्पित तारीख को 10 वर्ष और बढ़ाकर पहली जनवरी 1964 कर दिया जाए।

- (ग) पूजीगत लाभकर रिहायशी मकान की बिक्री पर भी देय होता है। वर्तमान कानून में यह व्यवस्था है कि यदि निर्धारित समय में दूसरा रिहायशी मकान खरीद लिया या बनवा लिया जाए तो उस हालत में, पूजीगत लाभों पर पूरी या आंशिक छूट मिल सकती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि नये रिहायशी मकान पर पूजीगत लाभ की कितनी रकम इस्तेमाल की गई है। आभूषणों या शेरों जैसी परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त पूजीगत लाभ के सम्बन्ध में इस प्रकार की रिहायश नहीं मिलती। किन्तु इस तरह का भेदभाव रखने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता। इस लिए यदि किसी भी परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त रकम को फिर से छ महीने के अन्दर-अन्दर शेयरों, बैंक जमा खातों, यूनित ट्रस्ट के यूनित्स अथवा अन्य तरजीही परिसम्पत्तियों में लगा दिया जाए तो उस पूजीगत लाभ के सम्बन्ध में मैं कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इस बात की व्यवस्था करने के लिए कि इस रिहायश का अनुचित उपयोग न हो, यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह परिसम्पत्ति, जिसमें बिक्री से प्राप्त रकम फिर से लगा दी गई है, कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक जरूर कब्जे में रखी जाएगी।

73 औद्योगिक उपक्रमों की रणनीति राष्ट्र के लिए भारी खिता का विषय बन गई है। किसी भी उद्योग में किसी बड़ निमोणकारी एकांक के बन्द हो जाने से उसका मूल्य समाज को चुकाना पड़ता है क्योंकि इससे उत्पादन और रोजगार को नुकसान पहुँचता है और इसके अलावा मूल्यवान् पूजीगत परिसम्पत्ति भी बर्बाद हो जाती है। इस संबंध में जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा हमेशा इस तरह के एकांकों को अपने हाथ में ले लेना इस समस्या का न तो कोई अत्याधिक संतोषजनक और न ही कोई मितव्ययतापूर्ण समाधान है। अपेक्षाकृत अधिक कारगर उपाय तो यह होगा कि कुछ प्रोत्साहन देकर तथा रण एकांकों को स्वस्थ एकांकों के साथ मिलाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके ऐसी सुविधा उपलब्ध की जाए जिससे कि रण औद्योगिक एकांक स्वेच्छा से स्वस्थ एकांकों के साथ मिला दिए जाए। तदनुसार यह व्यवस्था करने का विचार है कि जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार यह स्वीकार कर ले कि रण एकांक को स्वस्थ एकांक में मिला देना लोक हित में है, उन मामलों में जो कम्पनी रण एकांक को अपने में मिला लेती है उस कम्पनी की सचित हानियों और असमाविष्ट मूल्य ह्रास को आगे ले जाए जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उसे उस कम्पनी के हाथ में प्रतिसन्तुलन के लिए रख दिया जाएगा जिसका विलय किया गया है।

74. कम्पनियों को ग्राम कल्याण और ग्रामोत्थान के कामों में हाथ बटाने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखता हूँ कि इन कम्पनियों द्वारा ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रमों पर किए गए खर्च की, उनके कर योग्य लाभों का हिसाब लगाने समय, कटौती करने की अनुमति दी जाएगी।

75. देहाती इलाको में छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा देने के उद्देश्य से, मैं उन उद्योगों पर तर्जनीही कर व्यवस्था लागू करना चाहता हूँ जो इस तरह के इलाको में स्थापित किए गए हों और जो निर्माण का काम 30 जून, 1977 के बाद शुरू करेंगे। इस तरह के उपक्रमों को अपने कर योग्य लाभों का हिसाब लगाने में अपने लाभ के 20 प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करने का अधिकार होगा। उपक्रम जिस वर्ष से निर्माण का काम शुरू करेगा उस वर्ष से लेकर दस वर्षों तक प्रति वर्ष उसे यह रिआयत उपलब्ध की जाएगी।

76. पिछले एक वर्ष व्यवस्था की गई थी जिसके अन्तर्गत कम्पनियों को यह विकल्प दिया गया था कि वे आयकर पर 5 प्रतिशत अधिभार देने के बजाय उतनी ही रकम पांच वर्षों की अवधि के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास जमा करा सकते हूँ। मैं इस विकल्प को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। तदनुसार बजट में 56 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर की प्राप्ति दिखाई गई है।

77. पूर्ण प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले दान की राशि के संबंध में दान देने वाले व्यक्ति की सकल कुल आय के 10 प्रतिशत तक की रकम पर कर नहीं लगता; किन्तु कर से मुक्त की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है। यह महसूस किया जाता है कि यह अधिकतम सीमा अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक है और यह उचित पूर्ण प्रयोजनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उदारतापूर्वक दान दिए जाने के मामले में दाताओं को निरुत्साहित करती है। तदनुसार मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ा कर 5 लाख रुपए कर दी जाए।

78. भारतीय तकनीशनों को भारत से बाहर विदेशों में सेवा करने पर किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी उद्यम से जो पारिश्रमिक मिलता है उसके पचास प्रतिशत भाग को आयकर से छूट दी जाती है। जब नियोजक एक भारतीय उपक्रम हो तब यह रियायत न दी जाए, हमें यह बात न्यायसंगत नहीं जान पड़ती। तदनुसार मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस रिआयत का दायरा बढ़ा दिया जाए ताकि यह भारत से बाहर भारतीय उपक्रम द्वारा अपनी किसी शाखा अथवा कार्यालय में नियुक्त किए गए भारतीय तकनीशनों पर भी लागू हो सके।

79. छोटे लाभार्थी में से कर की रकम काट लेने से संयुक्त पूंजी कम्पनियों में पूंजी लगाने वाले कई छोटे छोटे निवेशकों को भारी कठिनाई होती है। इस उद्देश्य से कि इस तरह के निवेशकों, खासकर देहाती इलाको के निवेशकों को कोई असुविधा न हो, लाभार्थी में से स्रोत पर कर की रकम काट लेने की व्यवस्था को उन लोगों के मामले में समाप्त कर दिया जाएगा जिनको अदा की जाने वाली लाभार्थी की रकम 250 रुपए से अधिक न हो।

80. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 के द्वारा की गई एक व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ण अथवा धार्मिक न्यासों और संस्थाओं को अपनी रकमें आयकर अधिनियम में निदिष्ट कुछ रूपों में तथा तरीकों से निवेश करनी पड़ती है। जो न्यास अथवा संस्था पहली अप्रैल 1978 को अथवा इसके बाद शुरू होने वाले किसी लेखा-वर्ष में निवेश की इस निर्धारित प्रणाली को कही अपनाएंगी उसे आयकर से छूट नहीं दी जाएगी। इस संबंध में सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए तथा इस बात का सुनिश्चित करने के लिए कि नए उपबंधों के अनुरूप निवेश करने की प्रणाली में अपेक्षाकृत अधिक सुचारु तरीके से परिवर्तन किया जा सके, निवेश की नई प्रणाली को अपनाने की तारीख को तीन वर्ष बढ़ा देने, अर्थात् उसे पहली अप्रैल 1978 से बढ़ाकर पहली अप्रैल 1981 कर देने का प्रस्ताव है।

81. मैंने आयकर पर अधिभार बढ़ाने तथा धन कर की दरे बढ़ाने से होने वाली प्राप्तियों को जमा खाते में रख लिया है। व्यक्तियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों आदि के मामलों में 10,000 रुपए तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर देने के कारण राजस्व में जो हानि होगी उसे भी ध्यान में रखा गया है। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का प्रभाव यह होगा कि चालू वर्ष में केन्द्र को 92 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

82. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानून उत्तरोत्तर इतने अधिक पेचीदा हो गए हैं कि उन्हें आसानी से नहीं समझा जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि इन कानूनों को सरल तथा युक्तिसंगत बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि करदाता उन्हें तुरन्त समझ सकें, मुकदमेबाजी को कम किया जा सके और इस तरह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हित सिद्ध हो सके। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि इन कानूनों को लागू करने का शीघ्र निर्धारण करने और इन कानूनों के अन्तर्गत अपीलीय तथा अन्य कार्रवाइयां शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक अर्थोपयोगों की जाच की जाए। इसलिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को सरल और युक्तिसंगत बनाने की दिशा में सुझाव देने के लिए सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया गया है। मेरा इरादा यह है कि मैं समिति को वर्ष समाप्त होने से पहले ही अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहूंगा।

अप्रत्यक्ष कर

83 अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों की ओर जाता हूँ। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क संबंधी मेरे प्रस्ताव तीन श्रेणियों में आते हैं; पहली श्रेणी का संबंध अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए किए गए प्रस्तावों से है, दूसरी श्रेणी के प्रस्ताव उत्पाद-शुल्कों को कम करने या समाप्त करने से संबंधित हैं और प्रस्तावों की अंतिम श्रेणी शुल्क संबंधी ढांचे को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए है।

84 परवर्ती पांच मदों पर 10 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव है (i) हाथ औजार और छोटे औजार जिन पर पहले उत्पाद शुल्क नहीं लगता था, (ii) तोलने की मशीनें और तोलने के काटे (iii), हाथ घड़िया, दीवार घड़िया, और मेज घड़िया, (iv) बिजली की रोशनी की फिटिंग और (v), जूतों, धातुओं, कारों आदि के लिए पालिशें। एमीटलीन गैस पर भी 12 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। किन्तु हाथ औजारों और छोटे औजारों, बिजली की रोशनी की फिटिंग और पालिशों के लघु निर्माता अपने 1 लाख रुपए तक के उत्पादन के लिए शुल्क से मुक्त रहेंगे। आशा है कि इस प्रकार शुल्क लगाने के एक वर्ष में 11 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

85 जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, 1975 में एक प्रयोग के तौर पर उन वस्तुओं पर, जिन पर किसी विशिष्ट शीर्षक के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क नहीं लगते थे, 1 प्रतिशत की दर से सामान्य उत्पाद-शुल्क लगाया गया था। यह प्रयोग इस रूप में सफल रहा कि अनुचित रूप से किसी प्रकार का बोझ डाले बिना या परेशान किए बिना ही हम काफी बड़ी धनराशि अर्थात् 37 करोड़ रुपए एकत्र कर सके। जबकि हमें अतिरिक्त साधनों की जरूरत है, तो इस दर को बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर देना बहुत ही उपयुक्त मालूम होता है। उसके लगातार पड़ने वाले असर को कम करने के लिए ऐसे मामलों में कुछ प्रति-संतुलन कर दिया जाएगा जहां इन वस्तुओं का उपयोग ऐसा दूसरा सामान बनाने के लिए किया जाएगा जो खुद भी उत्पाद शुल्क के योग्य है।

86. यह सोचते हुए कि इस उत्पाद-शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत तरह तरह का सामान बनाने वाले बहुत से छोटे एकक आते हैं, मैंने यह व्यवस्था कर दी है कि ऐसे किसी भी एकक पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा जिसका वार्षिक कारोबार 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। यह छूट उस मौजूदा छूट के स्थान पर होगी जो कामगारों की संख्या पर आधारित है। मैं बिना बिजली के चलने वाले सभी एकको को भी इस शुल्क से मुक्त कर रहा हूँ।

87. इसके अलावा, छोटे समाचार-पत्रों को तो इस शुल्क से पहले ही मुक्त कर दिया गया है। अब इस छूट को मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। बड़े समाचार-पत्र 1 प्रतिशत की मौजूदा दर से शुल्क देने रहेंगे।

88. आशा है कि प्रस्तावों के इस वर्ग से एक वर्ष में कोई 30 करोड़ रुपए की निवल अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

89. अब मैं तम्बाकू उत्पादों पर आता हूँ जिन पर आए साल बोनस पड़ता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जब भी सिगरेटों का मूल्य बढ़ता है तब सिगरेटों का मूल्यानुसार शुल्क बढ़ जाता है। अब मौजूदा दरों की श्रेणी में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। ब्राण्ड वाली बीडियों के बारे में प्रस्ताव है कि एक रुपया प्रति हजार बीडी की मौजूदा शुल्क दर को बढ़ाकर दो रुपये प्रति हजार कर दिया जाए। अनुमान है कि इससे एक वर्ष में 45 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

90. सिनेमेटोग्राफ फिल्मों पर कर लगाने का वर्तमान तरीका प्रमुख रूप से फिल्म की लम्बाई और स्वरूप तथा प्रतियों की संख्या पर आधारित है। मैं इस आधार को बदल कर, मूल्य के आधार को अपनाते हुए, 10 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से सशोधित शुल्क लगाना चाहता हूँ। यह अधिक उचित कसौटी है।

91. पिगमेंट, पेंट, एनेमल, वॉनिश आदि पर इस समय जो मात्रानुसार शुल्क लगता है इसके स्थान पर मूल्यानुसार दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। इनको इस प्रकार समायोजित किया जा रहा है कि ऊँची लागत वाली मर्दों जैसे तेल मिश्रित पेंट, एनेमल, प्लास्टिक एमल्सन और वॉनिश पर शुल्क सामान्य रूप से लगभग 5 प्रतिशत की दर से बढ़ जाएगा जबकि सस्ती मर्दों जैसे कालिखो और सूखे डिस्टेंपर पर शुल्क में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इन परिवर्तनों से एक वर्ष में 418 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है।

92. मोटर यानों पर भी उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा रहा है? मोटर कारों पर शुल्क की दर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से लेकर $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक बढ़ा दी जाएगी। इसी प्रकार दो पहिये वाले और तीन पहिये वाले मोटर यानों पर शुल्क की दर 9 प्रतिशत से बढ़ाकर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है। चूंकि मैं मूल उपस्कर के रूप में सप्लाई किए गए टायरों, ट्यूबों और बैटरियों को, साथ ही, उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ, इसलिए दो और तीन पहिये वाले यानों के लिए शुल्क में निवल वृद्धि लगभग $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की होगी। इन परिवर्तनों से साल में 5.1 करोड़ रुपए का निवल राजस्व प्राप्त होगा।

93. अब मैं उत्पाद शुल्क घटाने या समाप्त करने के प्रस्तावों पर आता हूँ। इससे लाभ पाने वाला पहला उद्योग हैडलूम है। इस समय सिर्फ रीघे रील हैको में सप्लाई किया गया कोटन यार्न ही उत्पाद शुल्क से मुक्त है। अब क्रोस रील हैको में 20 एम काउन्ट तक के कोटन यार्न को

शुल्क मुक्त करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि फ्रांस रील हैको मे सप्लाई किये जाने वाले इससे ऊँचे काउन्टर के कोटन यार्न को भी 30 पैसे प्रति किलोग्राम तक शुल्क मुक्त किया जाए। इसके अलावा मैं विसकोस स्पन यार्न के संबंध में भी इसी प्रकार की रिश्मायतें देने का प्रस्ताव करता हूँ, क्योंकि इस समय हैडलूम क्षेत्र में इस तरह के यार्न की काफी बड़ी मात्रा में खपत हो रही है।

94. दूसरा लाभ पाने वाला उद्योग पावरलूम है। मैं उसे मौजूदा सम्मिश्रित उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसा करने से लगभग 80,000 पावरलूम लाइसेंसधारी उत्पाद शुल्क के नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे।

95. हैडलूम और पावरलूम कपड़ों को उत्पाद शुल्क देना पड़ता है जब उन पर कई तरह के परिष्करण की प्रक्रिया कर दी जाती है, लेकिन अगर विरजन, रंगाई और छपाई बिजली की सहायता के बिना की गई हो तो उन्हें छूट दी जाती है। यह प्रस्ताव किया गया है कि अब यह छूट बिजली की सहायता के बिना किए गए और सभी तरह के परिष्करण जैसे स्टेटरिंग और मॉमिस्ट्रिजिंग के लिए भी दी जाए।

96. यार्न क्रिपिंग उद्योग आज अत्यधिक क्षमता की वजह से पीड़ित है और क्रिम्पट यार्न और बेस यार्न की कीमतों के बीच जो अन्तर है उसके कारण वर्तमान शुल्क की दर को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए क्रिम्पड यार्न पर शुल्क को 10 रुपए प्रति किलोग्राम से घटाकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव है।

97. मैं पानी पंप करने वाले पावर पंपों पर लगने वाले शुल्क को 10 प्रतिशत में घटाकर 5 प्रतिशत करने और पावर टिलरो को सामान्य उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। ये दोनों रिश्मायतें छोटे किसानों के लिए खासतौर से लाभदायक सिद्ध होंगी।

98. कागज की छोटी मिलें कठिनाई के दौर से गुजरती रही हैं—यहां तक कि कुछ मिलें बन्द भी हो गई हैं। इसलिए मैं इन मिलों द्वारा उत्पादित कागज पर लगने वाले शुल्क को कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह राहत मिल की स्थापित क्षमता के आधार पर लगाए जाने वाले उत्पाद-शुल्क के 75 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक क्रमिक आधार पर दी जाएगी। यह रिश्मायत तभी दी जाएगी जब मिल कम से कम 50 प्रतिशत तक अपरम्परागत कच्चे माल और रद्दी कागज का उपयोग करेगी। कागज की अपेक्षाकृत बड़ी मिलें भी जब कम से कम 50 प्रतिशत तक अपरम्परागत कच्चे माल का उपयोग करेगी तब उन पर लगाने वाले उत्पाद शुल्क में 33½ प्रतिशत की दर से छूट दी जाएगी। इस रिश्मायत का उद्देश्य तेजी से कम हो रहे इमारती लकड़ी के साधनों को सुरक्षित रखना है।

99. दियासलाई उद्योग में छोटे कुटीर एकको को अपेक्षाकृत बड़े एकको के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन एकको में से ऐसे एककों को सहायता देने के लिए जो पंजीकृत सहकारी समितियों के सदस्य हो अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस रूप में प्रमाणित किए गए हों, मैं एक घूस दियासलाई की डिब्बियों पर 55 पैसे की मौजूदा रिश्मायत को दोगुना कर देने का प्रस्ताव करता हूँ? मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि इन एकको में रोजगार देने की बड़ी क्षमता है।

100. इस्पात के छोटे छोटे कारखाने भी कठिनाई में हैं। उनकी स्थिति तभी सुधारी जा सकती है जबकि उन्हें इस्पात के मुख्य कारखानों से, उत्पाद-शुल्क की अदायगी किए बिना, गलाने के लिए

इस्पात की नई छीजन उपलब्ध की जाएगी। अतः मैं इस्पात के मुख्य कारखानों से इस्पात के छोटे-छोटे कारखानों में गलाने के लिए कच्चे माल के रूप में निकाली गई इस्पात की पहचानने योग्य किस्म की नई छीजन को उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

101. बिजली के इंसुलेटिंग टेपो और स्लाटेड एगलों से कम राजस्व प्राप्त होता है और इसके अलावा वह अनेक छोटे-छोटे उत्पादकों से इकट्ठा किया जाता है। इसलिए मैं इन वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत विशिष्ट वस्तुओं की सूची में से निकाल देने का प्रस्ताव करता हूँ।

102. उबली हुई मिठाइयों, टाफियों, मिश्री आदि का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। चीनी, जो इन चीजों के लिए बुनियादी कच्चा माल है, उस पर तथा मिष्ठान्न उद्योग में उपयोग किए जाने वाले पैकिंग कागज और डिब्बों पर पहले से ही बहुत ज्यादा उत्पाद-शुल्क लगा हुआ है। इसलिए मैं इन मिठाइयों को भी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत विशिष्ट वस्तुओं की सूची में से काट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

103. हमारे उद्योगों में इलेक्ट्रानिक उद्योग एक विकासशील और होनहार उद्योग है और लघु उद्योगों के क्षेत्र के अन्तर्गत इस उद्योग में विकास की भारी गुंजाइश है। विभिन्न प्रकार की प्रस्तावित रिआयतों का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सहायता दी जाए। इस समय इलेक्ट्रानिक की वस्तुओं पर अलग अलग आधार पर शुल्क लगता है, कुछ वस्तुओं पर मालानुसार शुल्क तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर मूल्यानुसार शुल्क लगता है। अब इन सभी मदों पर मूल्यानुसार शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव है। रेडियो और ट्रांजिस्टर सेट, टेप रिकार्डर, टेप रिकार्डर एवं रेडियो, स्टीरियो तथा हाइ-फाई संगीत यंत्र का उत्पादन करने वाले बड़े निर्माता, वस्तु तथा कारखाना कीमत के आधार पर 15 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत की तक मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क की भ्रदायगी करेंगे। छोटे निर्माताओं को उत्पाद-शुल्क में मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की दर से रिआयत देने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह है कि वे मूल्यानुसार शून्य से लेकर 20 प्रतिशत तक की दर से उत्पाद-शुल्क देंगे।

104. अनुभव से पता चला है कि यदि उत्पाद-शुल्क के ढांचे की न्यायसंगत तरीके से समायोजित किया जाए तो उससे इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्माताओं को अपनी वस्तुओं की कीमतें कम करने के लिए जोरदार प्रोत्साहन मिलता है। हम अनुभवजन्य इस प्रयोग का और आगे जारी रखने का प्रस्ताव करते हैं। दूर दर्शन सेटों के मामले में अब से 5 प्रतिशत की रिआयती दर उन्हीं टो पर लागू होगी जिनका स्क्रीन 36 सेंटीमीटर से अधिक होगा और जिनकी कारखाना कीमत 1800 रुपए की मौजूदा सीमा के स्थान पर 1600 रुपए अथवा इससे कम होगी। टेप रिकार्डरों के मामले में रिआयती दर तभी लागू होगी जब उनकी दर कारखाना कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्ट्रानिक कैल्क्युलेटर्स के मामले में भी रिआयती दर उन कैल्क्युलेटर्स पर लागू होगी जिनकी कारखाना कीमत 175 रुपए से ज्यादा नहीं होगी।

105. अब मैं, उत्पाद-शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में अपने प्रस्तावों की व्याख्या करता हूँ। इस समय हम कई छोटे-छोटे कटौत करने वालों से ऊनी धागे पर उत्पाद-शुल्क इकट्ठा करते हैं। इसमें कम अप्रवचन और कई तरह के दुष्कर्म होते हैं। अतः ऊनी धागे पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क के स्थान पर कच्ची ऊन, रूई ऊन और चिथड़ों के आयात पर लगने वाले सीमाशुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा जाता है। ऊन टापो के संबंध में भी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्ष का कम से कम अप्रवचन हो, उत्पाद-शुल्क की दर को प्रति किलोग्राम 10 रुपए से घटा कर प्रति

किलोग्राम 5 रुपए कर देने और इस कमी को कच्ची ऊन पर आयात-शुल्क बढ़ा कर पूरा करने का प्रस्ताव है। इन दोनों उपायों से वे ऊनी कपड़े सस्ते हो जाएंगे जिनमें देशी ऊन का प्रयोग किया जात है।

106. इस्पात के अधिकतर रीरोलर ऐसे बार, राड और एगल आदि तैयार करते हैं जिनपर, डलोपर पहले ही अदा किए गए शुल्क के अलावा, 130 रुपए प्रति मेट्रिक टन की दर से उत्पाद-शुल्क लिया जाता है। 130 रुपए प्रति मेट्रिक टन की इस शुल्क दर को रीरोलरो पर न लगा कर, रुई बनाने वाली अर्थात् मुख्य इस्पात कारखानों अथवा छोटे इस्पात कारखानों पर लगाने का प्रस्ताव है।

107. सूती धागे पर उत्पाद-शुल्क लगाने की मौजूदा योजना एक खंड पद्धति पर आधारित है, जहाँ कहीं काउंटों को एक साथ मिला दिया गया है, और जब सूत का काउंट एक खंड से बढ़ कर दूसरे खंड में आ जाता है तब उत्पाद-शुल्क की दर तेज से बढ़ जाती है। शुल्क के इस ढाँचे की वजह से ऊंची दर पर शुल्क की अदायगी से बचने की प्रक्रिया के अन्तर्गत सूत की कताई कम होती है और इस तरह रुई का दुरुपयोग होता है। इस संबंध में कर अपवचन को रोकना भी आसान नहीं है। जहाँ सूत के काउंट में प्रत्येक यूनिट के बढ़ जाने पर शुल्क दर धीरे धीरे बढ़ जाती है वहाँ इन दुष्टियों को दूर करने के लिए नई दर अनुसूची लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। नई दरों में आधा पैसा प्रति काउंट के हिस्सा से शुल्क शामिल है जिसका प्रयोजन सरकार के उस घाटे को पूरा करना है जो उसे पावरलूमों और हैंडप्रोसेसरो को शुल्क मुक्त कर देने के कारण हुआ है, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है। व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के एक और उपाय के रूप में, विस्कोस के करते हुए सूत (यार्न) पर उत्पाद शुल्क उन्हीं दरों से लगाया जाएगा, जिन दरों से रुई के सूत पर उत्पाद-शुल्क लगाया जाता है।

108. पिछले वर्ष सूती कपड़ों पर मूल्यानुसार दरों पर कर लगाए जाने की प्रणाली लागू की गई थी। कर की दरें, कपड़े में इस्तेमाल किए गए सूत के काउंट के अनुसार अलग अलग थी। इस व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के लिए, मेरा विचार मूल्यानुसार कराधान करने का है, चाहे सूत का काउंट कुछ भी क्यों न हो और इस व्यवस्था में काफी ज्यादा बुद्धिशीलता का तत्व भी अंतर्निहित होगा। शुल्कों का यह ढाँचा हम नरह में तैयार किया गया है कि सूतों पड़े तथा सूत से लगभग उतना ही राजस्व प्राप्त हो, जितना कि इस समय, इन वस्तुओं से कुल मिलाकर एकत्रित किया जाता है।

109. जहाँ तक पावरलूमों से तैयार किए गए कपड़े का संबंध है, इस पर अभी छूट मिलेगी जब इसे धूसर रूप में ही बेच दिया जाएगा अथवा इसका परिष्करण हैंडप्रोसेसरो के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जब परिष्करण का कार्य बिजली की चालित प्रोसेसरो से किया जाएगा, तो शुल्क की दर, मिल के कपड़े के संबंध में लागू होने वाली सूत तथा कपड़ा संबंधी मिलीजुली दर के 50 प्रतिशत के बराबर होगी।

110. सूत तथा कपड़े की नामकरण पद्धति और वर्गीकरण के संबंध में भी एक और बड़ा सुधार करने का विचार है। आगे से, सूत अथवा कपड़े को साधारणतः उस रेशे (फाइबर) के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, जो वजन के हिसाब से प्रमुखता रखता है। नई प्रणाली अपेक्षाकृत सरल होगी और इस से बहुत-सी व्यवहारिक कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। इसके अलावा, कुल फाइबर, में उसके छोटे भाग तक पोलियेस्टर फाइबर, के सम्मिश्रण से सूत का वर्गीकरण नहीं बदलेगा। इस से वस्त्र उद्योग और ज्यादा पोलियेस्टर फाइबर का इस्तेमाल कर सकेगा और तैयार सूत पर और ज्यादा शुल्क भी नहीं लगेगा। उसके साथ ही इस से उस बहु-तर्तुक (मल्टीफाइबर) नीति को भी समर्थन मिलेगा जिसका विकास सरकार कर रही है।

111. छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के परिणाम स्वरूप, 1976-77 से सहायक उत्पाद शुल्कों की रकम भी राज्यों के साथ उसी प्रकार से बांट ली जाएगी जिस तरह से आधारीक उत्पाद शुल्कों की रकम को विभाजित किया जाता है। अतः सहायक शुल्कों को अलग से लगाने का औचित्य अब नहीं रहा है। कर ढाँचे को सरल बनाने और अनावश्यक हिसाब-किताब करने की प्रक्रिया को समाप्त करने के उद्देश्य से, मैंने सहायक उत्पाद शुल्कों को आधारीक उत्पाद शुल्कों के साथ मिला देने का फैसला किया है।

112. मैंने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ में भी कई मामूली परिवर्तन किए हैं जिनका यहाँ पर मैं विस्तार से उल्लेख नहीं करूँगा। किन्तु बजट पत्रों में, निस्संदेह, इन परिवर्तनों का पूरा ध्यान दिया गया है।

113. अनुमान है कि अनिवार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों से एक वर्ष में 106.3 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। जो कुल रिआयतें दी गई हैं उनके आधार पर एक वर्ष में 15.7 करोड़ रुपए की रकम नहीं मिलेगी। इस प्रकार अनुमान है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में 90.6 करोड़ रुपए की निवल वार्षिक वृद्धि होगी। लेकिन उन के धागे तथा उन पर लगने वाले शुल्क को आयात के क्षेत्र में अंतरित कर दिये जाने के कारण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शीर्षक से सीमा शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत 17.0 करोड़ रुपए का अन्तरण होगा और इस प्रकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत 73.6 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि होगी। इस से, पूरे वर्ष में केन्द्र को 53.8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा जबकि राज्यों का हिस्सा 19.8 करोड़ रुपए का होगा।

114. आखिर मैं मैं सीमा शुल्कों की ओर आता हूँ जिनके बारे में मुझे थोड़े से ही प्रस्ताव प्रेष करने हैं। हमारे देश में घड़ियों का जो उत्पादन होता है, उस से घरेलू मांग की अच्छी तरह से पूर्ति होती है। सब जानते हैं कि इसके परिणामस्वरूप, काफी बड़ी तादाद में विदेशी घड़ियाँ देश में चोरी-छिपे लाई जाती हैं। इसी बात को देखते हुए, सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल लिमिटेड की मार्फत घड़ियों के आयात की अनुमति देकर बाकी की कमी को पूरा करने का फैसला किया है। इस ध्येय से कि देश में तैयार की गई घड़ियाँ और आयातित घड़ियाँ जनता को मुनासिब कीमतों पर उपलब्ध हो सकें, मैं घड़ियों के पुर्जों पर तथा घड़ियों पर आयात शुल्कों को, 120 प्रतिशत मूल्यानुसार से कम करके, 50 प्रतिशत मूल्यानुसार कर रहा हूँ।

115. मैं अबकारी कागज पर भी आयात शुल्क को 5 प्रतिशत मूल्यानुसार से कम करके 2½ प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

116. मैं अब कुछ ऐसे प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा जिनका उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और देश के उद्योग धन्धों की प्रतियोगितात्मक क्षमता में वृद्धि करना है। कुछ हद तक प्रतियोगितात्मक तत्व का समावेश करने के लिए यह विचार है कि देशी दृष्टिकोण से पूर्ववर्ती छानबीन किए बिना ही पुजीगत वस्तुओं की कुछ चुनी हुई मदों के आयात की अनुमति दे दी जाए। इसी के साथ साथ, इस उद्देश्य से कि भारतीय पूजीगत वस्तु उद्योग विदेशी प्रतियोगिता का और ज्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला कर सकें, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कुछ बड़े आकार के बिजली के मोटरों, जनित्रों तथा ट्रांसफार्मरों के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली तांबे की तार-छड़ों के आयात शुल्क की दरों को 5,600 रुपया प्रति मेट्रिक टन सहित 45 प्रतिशत की मौजूदा स्तर से घटा कर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। इसी प्रकार ठण्डी प्रक्रिया से तैयार की जाने वाली "नान-मैन-ओरि-एण्टिड" चद्दरो, मिश्र इस्पात, औजारी इस्पात, विशेष इस्पात, और हाई कार्बन इस्पात के शुल्क की दर को भी 75 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का विचार है। इसके अलावा, स्टेनलैस

स्टील की प्लेटों, चूददरो तथा 16 गेज की या और मोटी पट्टियों (स्ट्रिप्स) पर, जिनका इस्तेमाल पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है और जिन पर गेज के अनुसार इस समय 120 प्रतिशत या 320 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है, केवल 40 प्रतिशत आयात शुल्क लिये जाने का विचार है। बर्तनों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले 22 गेज के या उससे भी पतले स्टेनलेस स्टील पर, जिस पर इस समय 320 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है, केवल 120 प्रतिशत आयात शुल्क लिया जाया करेगा। आयातित उत्पादों की री-रोलिंग की सभावना को हिसाब में लेते हुए, मध्यवर्ती गेजों के संबंध में शुल्कों की अलग अलग दरें निर्धारित करने का विचार है। अनुमान है कि आयात के वर्तमान स्तर के अनुसार, तांबे तथा इस्पात की इन वस्तुओं के शुल्कों में की गई कमी से 36.25 करोड़ रुपए के राजस्व की कमी होगी।

117. सीमा शुल्कों में जिन वृद्धियों के प्रस्ताव मैने किए हैं उनके परिणामस्वरूप वर्ष भर में 15.5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। जो राहत दी गई है वह एक वर्ष में 37.7 करोड़ रुपये की होगी जिसके परिणामस्वरूप 22.2 करोड़ रुपए की निवल कमी होगी। लेकिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शीर्षक से सीमा शुल्क शीर्षक के अन्तर्गत जो 17 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया है उसको हिसाब में लेने से, इन बजट प्रस्तावों से सीमा शुल्क राजस्व में एक वर्ष में कुल मिलाकर 5.2 करोड़ रुपए की कमी होगी।

118. सघीय उत्पाद शुल्कों तथा सीमा शुल्कों, दोनों से केन्द्र को एक वर्ष में कुल मिला कर 48.6 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी। चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में 38.2 करोड़ रुपए की आमदनी होगी।

119. मेरे प्रस्तावों से चालू वर्ष में केन्द्र के लिए कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। मैंने जिस 202 करोड़ रुपए के घाटे का पहले उल्लेख किया है वह इस प्रकार घटकर 72 करोड़ रुपए रह जाएगा। यह अपेक्षाकृत छोटी रकम है और इस में कोई स्फीतिकारी प्रभाव होने की सभावना नहीं है।

उपसंहार

120. इसके साथ ही मैं अपने अग्रमाध्य कार्य की समाप्ति पर पहुंच गया हूं। इस बजट को तैयार करने में मेरा उद्देश्य यही रहा है कि उत्पादन तथा रोजगार की वृद्धि की अधिक ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थ-व्यवस्था को प्रेरणा मिले और इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक प्रगति के फल भी, जहां तक संभव हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त हों। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि, लघु तथा ग्रामउद्योग और आधारभूत ग्रामीण ढांचे में पूंजी-निवेश पर बल दिया गया है। मैंने जो कर प्रस्ताव रखे हैं, उनका आशय राष्ट्रीय बचत को बढ़ाना है, और साथ ही आय तथा धन सम्बन्धी विषयों को कम करने में कर-व्यवस्था की भूमिका को मजबूत करना है। मैंने अग्रदानी आदमी के लिए—चाहे वह किसान हो, कारीगर हो अथवा टेक्नोक्रेट हो—और ज्यादा व्यापक अक्षरों में प्रदान करने के संबंध में खास ध्यान रखा है। यह कहना तो व्यर्थ होगा कि हम एक ही प्रयास में अपने देश के विशाल जनसमूह की प्रसूत शक्ति का सम्पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। किन्तु शुभ्रागत तो करनी ही थी। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि इस बजट में यह शुभ्रागत कर दी गई है।

121. मेरे दिल ने आजादी पर बल दिया है। लेकिन आजादी का मतलब यह नहीं है कि किसी को भूखों मरने अथवा अवांछित महसूस करने की छूट प्राप्त है। व्यापक गरीबी तथा बेरोजगारी उन लोगों

को नीचे गिराती है जिनको यह झेलनी पड़ती है और उन व्यक्तियों को नीचे बनाती है जो इन्हे सहन कर जाते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि ये दोनों बलाएँ जल्दी से जल्दी खत्म कर दी जाएँ। हमारे सामने एक लम्बा और कठिन मार्ग है। लेकिन इस बात में कुछ भी सन्देह नहीं है कि हम अपने ध्येयों और आदर्शों को पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि हम ठीक रास्ते पर हैं और यह बजट इस ठीक रास्ते पर उठाया गया हमारा पहला कदम है, चाहे यह कदम छोटा ही क्यों न हो।

BUDGET 1977-78

SPEECH OF MINISTER OF FINANCE

17TH JUNE, 1977

(PART "B")

DIRECT TAXES

62. I shall now address myself to the task of formulating proposals for covering the deficit to the extent feasible.

63. The proposals, in so far as direct taxes are concerned, which I am presenting before you, are designed to increase corporate savings, channel more funds into productive investment, accelerate the pace of industrial growth and, at the same time, strengthen the redistributive role that direct taxes, to my mind, must be made to play.

64. In so far as indirect taxes are concerned, I have endeavoured to ensure that my proposals do not impinge on the necessities of life. There, I have sought to raise resources, in the main, from the less essential or luxury items, while giving relief to some deserving sectors, and simplifying and rationalising the central excise tariff structure generally.

65. In fulfilment of an assurance in the Janata Party manifesto, I propose to provide that no income-tax shall be payable by individuals and Hindu undivided families whose taxable income does not exceed Rs. 10,000. In order, however, to keep the sacrifice of revenue to the minimum the nil rate slab of income is being retained at Rs. 8,000. Hence, where the taxable income exceeds Rs. 10,000, the excess over Rs. 8,000 will be charged to tax as at present subject to the grant of marginal relief in cases where the taxable income exceeds Rs. 10,000 by a small margin.

66. I do not propose to make any change in the basic rates of income-tax. However, in view of the imperative need to raise additional resources, I propose to increase the rate of surcharge on income-tax in the case of all categories of taxpayers, except companies, from 10 per cent. to 15 per cent. With the increase in the rate of surcharge, the maximum marginal rate of personal income-tax will now be 69 per cent., as against 66 per cent. at present.

67. It is my feeling that wealth-tax rates were reduced in the Budget of 1976 to an unjustifiable extent. If the essential objective of a wealth-tax is to be achieved, it must be so devised that while it does not become oppressive and counter-productive, it does have an effect on excessive accumulation of wealth in individual hands. In this view of the matter I propose to raise the rates of wealth-tax. The existing rate of half per cent will continue unchanged on the first Rs. 25 lakhs of net wealth, but for the higher slabs there will be an increase of half a per cent. over the existing rates, while in the highest slab of over Rs. 15 lakhs, the new rate will be three and a half per cent, that is, an increase of one per cent. over the existing rate. There will be corresponding changes in the rates applicable to Hindu undivided families having one or more members with net wealth exceeding Rs. 1 lakh. The new rate schedule will come into force from the current assessment year and will thus supersede the changes made last year in the rate schedule. These changes will result in an additional revenue of about Rs 10 crores in 1977-78.

68. As Hon'ble Members are aware, Government have already dispensed with the Compulsory Deposit Scheme in its application to additional dearness allowance as from 6th May, 1977. Having regard, however, to the state of the economy and the inflationary pressures that exist, I propose to continue the Compulsory Deposit Scheme for Income-tax Payers for another two years.

69. With a view to stimulating industrial development and economic growth, I consider it desirable to widen the scope of the scheme of investment allowance introduced last year. That scheme has unfortunately not laid down any well-defined and clear criteria for selecting industries to which the benefit of the concession was to be extended. This made it difficult to explain to those claiming eligibility why some industries had been given the benefit, while it was denied to others. Since there is a need for encouraging generation of internal resources for financing investment, I consider it best to extend the scope of investment allowance to all industries except those which are engaged in the manufacture of specified low priority items such as cigarettes, cosmetics and alcoholic beverages. This measure will be of great benefit to the economy.

70. In order to promote scientific and technological self-reliance, I propose to provide an incentive to the users of technical know-how developed in our country. It is accordingly proposed to grant investment allowance at the higher rate of 35 per cent. on machinery and plant installed for the manufacture of any article made in accordance with know-how developed in Government laboratories, public sector companies and universities.

71. From the point of view of maximising expansion of industry, I can see little merit in compelling closely-held industrial companies to distribute a high percentage of their net profits as dividends. I propose, therefore, to exempt such companies from the requirement of compulsory distribution of dividends. I do not propose to extend this relief to all other kinds of closely-held companies.

72. It is my belief that the present structure of capital gains taxation stands in the way of adequate monthly or investible resources, and perpetuates investment in low priority assets. In this view, I am proposing certain changes in our existing scheme of capital gains taxation.

- (a) At present capital gains arising from the transfer of a capital asset held by a taxpayer for a period exceeding 60 months alone are entitled to concessional tax treatment. With a view to improving mobility, I propose to reduce the holding period to 36 months.
- (b) In respect of capital assets acquired prior to the 1st of January, 1954, a taxpayer has the option of adopting the fair market value of the asset on 1st January, 1954 in place of the actual cost of acquisition. Determination of the fair market value of a capital asset with reference to a date more than 23 years ago presents practical difficulties. Moreover, capital gain arising from the transfer of assets held over a length of time is, in a world of rapid and continuing inflation, to a great extent illusory in nature. On the whole, therefore, it seems to me desirable to advance the notional date by 10 years, namely, to 1st of January, 1964.
- (c) Capital gains tax is payable on the sale of a residential house. The existing law provides that if another residential house is either purchased or constructed within a specified time, then the capital gains can be wholly or partially exempted depending upon the amount of capital gains utilised on the new residential house. Similar concessions are not available in respect of capital gains arising from sale of assets, such as jewellery or shares. I see no reason for drawing such a distinction. Accordingly, I propose to exempt the capital gains from tax, if the sale proceeds of any asset are reinvested within six months in shares, bank deposits, units of the Unit Trust or other preferred assets. In order to prevent abuse of this concession, it is required that the assets in which the sale proceeds have been reinvested are held for a period of not less than three years.

73. Sickness among industrial undertakings is a matter of grave national concern. Closure of any sizeable manufacturing unit in any industry entails

social costs in terms of loss of production and employment, and also waste of valuable capital assets. Experience has shown that taking over of such units by Government is not always the most satisfactory or the most economical solution. A more effective course would be to facilitate the voluntary amalgamation of sick industrial units with sound ones by providing certain incentives and by removing impediments in the way of such amalgamation. It is accordingly proposed to provide that where an amalgamation is accepted by the Central Government to be in public interest, the accumulated losses and unabsorbed depreciation of the amalgamating company will be allowed to be carried forward and set off in the hands of the amalgamated company.

74. With a view to encouraging companies to involve themselves in the work of rural welfare and uplift, I propose to provide that expenditure incurred by them on approved programmes of rural development will be allowed to be deducted in computing their taxable profits.

75. In order to give a direct stimulus for the setting up of small-scale industrial undertakings in rural areas, I intend to accord preferential tax treatment to industries which are set-up in such areas, and which begin their manufacturing activity after 30th June, 1977. Such industrial undertaking will be entitled to a deduction in the computation of their taxable profits of an amount equal to 20 per cent. of the profits. The concession will be available for each of the ten years commencing from the year in which the undertaking begins its manufacturing activities.

76. Under a provision made last year, companies were given the option, instead of paying 5 per cent surcharge on income-tax, to deposit an equivalent amount with the Industrial Development Bank of India for a period of five years. I propose to withdraw this option. The Budget accordingly takes credit for an additional tax receipt of Rs. 56 crores on this account.

77. The amount of donations for charitable purposes qualifying for tax exemption is limited to 10 per cent of the gross total income of the donor, subject further to a monetary ceiling of Rs. 2 lakhs. It is felt that this ceiling is unduly restrictive and only discourages more liberal donations to deserving charities. I propose accordingly that the monetary ceiling be raised from Rs. 2 lakhs to Rs. 5 lakhs.

78. Fifty per cent. of the remuneration received by Indian technicians from a foreign Government or a foreign enterprise for services rendered outside India is exempt from income-tax. We cannot justifiably deny this concession when the employer happens to be an Indian concern. I propose accordingly to enlarge the scope of this concession to cover Indian technicians employed by Indian concerns in any branch or office outside India.

79. Deduction of tax from small dividends has been a source of considerable hardship to a large number of small investors in joint stock companies. With a view to avoiding inconvenience to such investors and in particular to investors from rural areas, the requirement of deduction of tax at source from dividends will be waived in cases where the dividend paid does not exceed Rs. 250.

80. Under a provision made by the Taxation Laws (Amendment) Act, 1975, charitable or religious trusts and institutions are required to invest their funds in certain forms and modes specified in the income-tax Act. Any trust or institution which does not conform to the prescribed pattern of investment in any accounting year commencing on or after 1st April, 1978 would lose exemption from income-tax. Having regard to practical difficulties involved and to ensure a more orderly change-over in their pattern of investment in line with the new provisions, the date for change-over to the new investment pattern is proposed to be extended by three years, i.e., from 1st April, 1978 to 1st April, 1981.

81. I have taken credit for increasing the surcharge on income-tax and increasing the rates of wealth-tax. The loss of revenue involved in exempting individuals, Hindu undivided families, etc. with an annual income up to Rs. 10,000 has also been taken note of. The overall effect of all the direct tax proposals would be a gain to the Centre's revenue of Rs. 92 crores in the current year.

82 As Hon'ble Members are aware, the direct taxes statutes have become increasingly complicated and incomprehensible over the years. It is, therefore, necessary to take immediate action for the simplification and rationalisation of these laws with a view to making them readily intelligible to the taxpayers, reducing litigation, and, thus, subserving the interest of the national economy. It is also necessary to examine ways and means of improving the administration of these laws and expediting assessment appellate and other proceedings under these laws. It has, therefore, been decided to appoint a Committee of eminent experts to make recommendations for the simplification and rationalisation of the direct tax laws. It is my intention to ask the Committee to submit its report before the end of the year.

INDIRECT TAXES

83 Now I come to my proposals with regard to indirect taxes. My proposals concerning central excise fall into three categories, the first relates to proposals for raising additional resources, the second to reduction or abolition of excise duties, and the last set of proposals seeks to rationalise and simplify the duty structure.

84 A 10 per cent excise duty is proposed to be levied on the following five items: (i) hand tools, and small tools not already excisable, (ii) weighing machines and weigh bridges, (iii) watches, clocks and time-pieces, (iv) electric light fittings and (v) polishes for footwear, metals cars, etc. It is also proposed to levy an excise duty of 12 per cent on acetylene gas. Small scale manufacturers of hand tools and small tools, electric light fittings and polishes, will, however, be exempted in respect of their production up to Rs 1 lakh. These levies are expected to yield a revenue of Rs. 11 crores in a year.

85 As Hon'ble Members are aware in 1975 as an experimental measure a 1 per cent general excise duty was levied on commodities which did not attract excise duties under any specific heads. The experiment has succeeded in the sense that without imposing any undue burden or harassment we were able to collect an appreciable sum of money, namely Rs 37 crores. When we stand in need of additional resources, it seems eminently suitable to raise this rate to 2 per cent. In order to minimise the cascading effect a set off will be given where these goods go into the manufacture of other goods that are themselves excisable.

86 Realising that under this excise head fall a large number of small units producing a variety of goods I have provided that no duty will be levied on any unit whose annual turn over does not exceed Rs 30 lakhs. This will replace the existing exemption based on the number of workers. I am also exempting all non-power operated units from this levy.

87. Further, small newspaperers have already been exempted from this levy. It is now proposed to extend this exemption to medium newspapers also. The big newspapers will continue to pay duty at the existing rate of 1 per cent.

88 The net additional yield from this group of proposals is expected to be of the order of Rs 30 crores in a year.

89. I now come to the hardy annual namely tobacco products. At present the rate of *ad valorem* duty on cigarettes increases as the value of cigarettes goes up. The progression in the existing rates is now proposed to be raised. In regard to branded birds it is proposed to raise the existing duty of rupee one per thousand to rupees two per thousand. These levies are estimated to yield an additional revenue of Rs 45 crores in a year.

90 The present system of taxing cinematograph films is based primarily on the length and the nature of the film and the number of prints. I intend changing the basis and adopting the value criterion, the revised duty being 10 per cent *ad valorem*. This is a much fairer criterion.

91 The present specific rates of duty on pigments, paints, enamels, varnishes etc. are proposed to be replaced by *ad valorem* rates. These are being so adjusted that the duty on the high cost items such as oil-bound paints, enamels, plastic emulsions and varnishes will increase by about 5 per cent generally, while that on the cheaper items like blocks and dry distemper will remain more or less unchanged. These changes are estimated to yield Rs 48 crores in a year.

92 The excise duty on motor vehicles is also being raised. The rate of duty on motor cars is to go up by $2\frac{1}{2}$ per cent to $17\frac{1}{2}$ per cent. Similarly, the rate of duty on two-wheeler and three-wheeler motor vehicles is proposed to be raised from 9 per cent to $12\frac{1}{2}$ per cent. Since I propose simultaneously to exempt from excise duty tyres, tubes and batteries supplied as original equipment, the net increase in duty for the two and three wheelers will be about $2\frac{1}{2}$ per cent. These changes will yield a net revenue of Rs 51 crores annually.

93. I come now to proposals for reduction or abolition of excise duties. The first industry to benefit is the handloom. At present only cotton yarn supplied in straight reel hanks is exempt from excise duty. It is now proposed to exempt also cotton yarn in cross reel hanks up to 20 exempt cotton yarn of higher counts in cross reel hanks to the extent of 30 paise per kilogram. Further, I propose to extend similar concessions in respect of viscose spun yarn, because the handloom sector is now consuming substantial quantities of that yarn.

94. The next beneficiary is the powerloom sector. I propose to exempt it from the existing compounded excise levy. This will free about 80,000 powerloom licensees from excise control.

95 Handloom and powerloom fabrics have to pay excise duty when they are subjected to various finishing processes, but an exemption is given if bleaching, dyeing and printing is done without the aid of power. It is now proposed to extend this concession to all other types of processing, such as stentering and mercerising done without the aid of power.

96 The yarn crimping industry is to-day suffering from excess capacity and the difference in price between crimped yarn and base yarn cannot sustain the present rate of duty. It is, therefore, proposed to reduce the duty on crimped yarn from Rs 10 per kilogram to Rs. 5 per kilogram.

97. I propose to reduce the duty on power driven pumps used for pumping water from 10 per cent to 5 per cent and to exempt power tillers from the general excise levy. Both these concessions will be of particular value to small farmers.

98. Small paper mills have been passing through difficult times—a few of them have even closed down. I therefore, propose to reduce the duty leviable on paper produced by these mills, the relief varying on a graded basis from 75 per cent to 50 per cent of the excise duty leviable, dependent upon the installed capacity of the mill. This concession will be subject to the use of non-conventional raw materials and waste paper to the extent of at least 50 per cent. Even larger paper mills if they use non-conventional raw materials to the extent of at least 50 per cent will get a duty relief of $33\frac{1}{3}$ per cent of the excise duty leviable. This concession is designed to conserve our fast depleting timber resources.

99 In the match industry, small cottage units are finding it difficult to compete successfully with the bigger units. To help such of these units as are members of registered cooperative societies or are certified as such by the Khadi and Village Industries Commission, I propose to double the existing concession of 55 paise for a gross of match boxes. I need hardly say that these units have a large employment potential.

100 Mini steel plants are also in difficulties. Their position could be improved if they were provided with fresh melting scrap from the main steel plants without payment of excise duty. I, therefore, propose to exempt from excise duty the identifiable types of fresh melting scrap cleared from the main steel plants as raw material for the mini steel plants.

101. The revenue from electric insulating tapes and slotted angles is low and further, has to be collected from a number of small producers. I, therefore, propose to delete these articles from the list of specific items in the Central Excise Tariff.

102. The production of boiled sweets, toffees, candies, etc has been going down. Sugar, which is a basic raw material, is already subjected to a high excise duty as also are packaging paper and containers used in the confectionery industry. I, therefore, propose to delete these confectionery articles also from the list of specific items in the Central Excise Tariff.

103. Electronics is one of our growing and promising industries, and offers great scope for development in the small scale sector. The various concessions that are proposed here are designed to help the growth of that sector. At present the duty on electronic items is on a varying basis, some being specific and others *ad valorem*. It is now proposed to make the basis uniformly *ad valorem*. The large manufacturers producing radios and transistor sets, tape recorders, tape recorder-cum-radios, stereos and hi-fi musical systems will pay duty varying from 15 per cent to 35 per cent *ad valorem*, depending on the item and the ex-factory price. It is proposed to give small manufacturers a uniform concession of 15 per cent *ad valorem* in the rate of duty, that is to say, the corresponding rates of duty that they will pay will vary from nil to 20 per cent *ad valorem*.

104 Experience has shown that a judiciously adjusted excise structure acts as a powerful incentive to manufacturers of electronic goods to reduce their prices. We propose to continue with this experiment further. In the case of TV sets the 5 per cent concessional rate of excise duty will henceforth be available only where the ex-factory price of a TV set with a screen exceeding 36 centimeters is Rs. 1600 or less, instead of the existing limit of Rs 1800. In the case of tape recorders, there will be a concessional rate if the ex-factory price does not exceed Rs. 500. For electronic calculators too, there will be a concessional rate for calculators if the ex-factory price does not exceed Rs 175.

105 I shall now expound my proposals concerning rationalisation. We are at present collecting excise duty on woollen yarn from a number of small spinners. This has led to evasion and other malpractices. It is, therefore, proposed to replace the excise duty leviable on woollen yarn by an increase in the customs duty at the stage of import of raw wool, waste wool and rags. As regards wool tops also, with a view to minimising evasion, it is proposed to reduce the present rate of excise duty of Rs 10 per kg to Rs 5 per kg and to make good the loss by increasing the import duty on raw wool suitably. Both these measures should result in making fabrics using indigenous wool cheaper.

106 Most steel re-rollers produce bars, rods, angles, etc. which attract an excise duty of Rs 130 per tonne in addition to the duty already paid on ingots. It is proposed to shift this duty of Rs 130 per tonne from the re-rollers to the ingot manufacturers, namely, the main steel plants or the mini steel plants.

107 The existing scheme of excise duty on cotton yarn is based on a slab system where several counts are grouped together, and provides for sharp increases in the rates of duty when the count of yarn increases from one slab to another. This duty structure encourages under-spinning of cotton in order to avoid payment of duty at the higher rate and leads to wasteful use of cotton. Evasion too is not easy to check. To remove these defects, a new schedule of rates has been proposed where the duty rises gradually with each unit increase in the count of yarn. The new rates include a duty of half a paise per count to enable Government to recoup the loss incurred by exempting powerlooms and hand processors from the excise duty, to which I have referred earlier. As a further measure of rationalisation, viscose spun yarn is proposed to be subjected to the same rates of excise duty as cotton yarn.

108. Last year, a system of *ad valorem* rates for cotton fabrics was introduced. The rates were, however, dependent on the count of the yarn used in the fabric. To rationalise the structure, I propose to adopt the *ad valorem* system irrespective of the count of the yarn and with a high degree of progression built into it. The new duty structure has been so devised as to yield approximately the same revenue from cotton fabrics and yarn as is collected at present from these items taken together.

109 As regards the cloth produced by powerlooms, it will be exempt if it is sold grey or is processed by hand processors, but if it is processed by independent power-operated processors, the rate of duty will be 50 per cent of the composite yarn and fabric rate paid by the mill fabrics.

110. A major reform which is proposed to be introduced relates to the nomenclature and classification of textile yarns and fabrics. Henceforth, yarn or fabric would ordinarily be classified on the basis of the fibre which predominates by weight. The new system will be much simpler and will remove many working difficulties. Further, the blending of polyester fibre up to one-sixth of the total fibre content will not change the classification of the yarn. This should enable the textile industry to use more polyester fibre without attracting higher duty on the yarn produced, and would be in furtherance of a multi-fibre policy which the Government is in the process of evolving.

111 Pursuant to the Government's acceptance of the recommendation of the Sixth Finance Commission, from 1976-77 onwards, auxiliary duties of excise have become shareable with the States in the same way as basic duties of excise. Thus, the justification for levying auxiliary duties separately has now disappeared. In order to simplify the structure and to eliminate unnecessary calculations, I have decided to merge the auxiliary duties with the basic duties of excise.

112 I have also carried out a number of minor modifications in the Central Excise Tariff which I do not propose to detail here. Full details of these changes are, of course, given in the Budget documents.

113 The total of the additional central excise levies is estimated to yield Rs. 108.3 crores in a year. The total concessions given will mean a sacrifice of Rs. 15.7 crores in a year. The net yearly increase in central excise levies is thus estimated at Rs. 90.6 crores. However, because of the transfer of the duty on woollen yarn and wool tops to imports, there will be a transfer of Rs. 17 crores from Central Excise head to Customs head, thus giving a net increase of Rs. 73.6 crores under the Central Excise head. Of this, the additional revenue accruing to the Central in a year will be Rs. 53.8 crores, while the States' share will be Rs. 19.8 crores.

114 Finally, I come to customs duties in respect of which I have to submit only a few proposals. Indigenous production of watches does not fully satisfy the domestic demand. As a result, considerable quantities of foreign watches are known to be smuggled into the country. Government have accordingly decided to make good the deficiency still remaining by allowing the import of watches through Hindustan Machine Tools Ltd. In order that the indigenously manufactured watches and imported watches are available to the public at reasonable prices I am reducing the import duty on watch parts and watches from 120 per cent to 50 per cent *ad valorem*.

115 I am proposing also to reduce the import duty on newsprint from 5 per cent to 2½ per cent *ad valorem*.

116 I would now make certain proposals designed to stimulate industrial growth and to enhance the competitiveness of our industry. In order to introduce a measure of competition, it is proposed to allow the import of certain selected items of capital goods without prior scrutiny from the indigenous angle. At the same time, in order to enable the Indian capital goods industry to meet foreign competition more effectively, I propose to bring down the rate of import duty on copper wire bars used for the manufacture of certain larger sized electrical motors, generators and transformers from the existing level of 45 per cent *plus* Rs. 5,600 per tonne to 40 per cent *ad valorem*. Similarly, the rate of duty on cold rolled non-grain-oriented sheets, alloy steel, tool steel special steel, and high carbon steel is also proposed to be brought down from 75 per cent to 40 per cent. Further, stainless steel plates, sheets and strips of 16 gauge and thicker which are used in the manufacture of capital goods and which are today charged to 120 per cent or 320 per cent duty depending on the gauge, are proposed in future to be charged to 40 per cent duty only. Utensil grade stainless steel of 22 gauge and thinner, which today attracts a duty of 320 per cent, will be charged to import duty at 120 per cent. Varying rates of duty are proposed to be fixed for the intervening gauges, taking into account the possibility of re-rolling imported products. It is estimated that the reduction in duties on these copper and steel items will mean a revenue sacrifice of the order of Rs. 36.25 crores at the existing level of imports.

117 The effect of the increases in Customs duties proposed by me will be an additional revenue of Rs. 15.5 crores in a year. The reliefs total Rs. 37.7 crores in a year thus resulting in a net reduction of Rs. 22.2 crores. But taking into account the transfer of Rs. 17 crores from the Central Excise head to the Customs head, the overall effect of the budget proposals on Customs revenue will be a reduction of Rs. 5.2 crores in a year.

118 Taking Union Excise duties and Customs duties together, the net yield for the Centre in a year will be Rs. 48.6 crores. The yield during the remaining part of the current financial year will be Rs. 38.2 crores.

119 My proposals will yield, in all, Rs. 130 crores for the Centre in the current year. The deficit of Rs. 202 crores which I mentioned earlier will, thus, be reduced to Rs. 72 crores. This is a relatively small amount and is unlikely to have any inflationary effect.

CONCLUSION

120. With this I have come to the end of my labours. My aim in this budget is to stimulate the economy into achieving a higher rate of growth of output and employment, and simultaneously to ensure that the fruits of economic progress are as widespread as possible. The emphasis on investment in agriculture, small and village industries and rural infrastructure is designed to achieve these objectives. My tax proposals seek to enlarge the pool of national savings while strengthening the role of taxation in reducing disparities of income and wealth. I have taken special care to widen opportunities for the small man—be he a farmer, an artisan or a technocrat. It would be futile to pretend that we can achieve at one stroke the full utilization of the latent energies represented by our vast human resources. But a beginning has to be made. I venture to think that this Budget marks such a beginning.

121. My party has emphasised liberty. But liberty does not mean freedom to starve and freedom to feel unwanted. Large-scale poverty and unemployment degrade those who have to suffer them, and debase those who tolerate them. We owe it to ourselves to see that these twin scourges are eradicated as quickly as possible. We have a long and a difficult road ahead of us. But there can be no doubt about our commitment to our goals and ideals. I believe we are on the right course, and this Budget represents the first step, however small, in that direction.

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

